1.00 P.M.

to on what lines we should act because things are becoming slowly very obvious to us. But there are certain formalities which we have to complete. When the Uttar Pradesh Government says that they are implementing the order, I cannot possibly say that their intention is not to implement the order. I cannot say that. It is all right for the hon. Members to say that their intentions are different. But so far as the Government of India is concerned, I will have to rely on the report given by the State Government and till we get the information, we have to wait. In spite of the assurance given by the State Government, either they are totally helpless or they are in collusion with other parties who are carrying on the work. If that be the position, there are certain things which should take place so that our records are clear that we are not trying to take any vindictive action against any political party. So that is exacly our positon. But unfortunately you are trying to impute motives to us as if we are colluding with the BJP. I can say with all the force at my command that there can be no question of collusion between the BJP and the Congress so long as such issues are there. These are major issues on which the real test is going to take place, whether we are going to stand by secularism or whether we are going away from it. That is the basic premise on which our credentials are going to be tested. Please, for God's sake, don't try to impute motives to us. When we are waiting for certain things, it is not because we are trying to avoid responsibility. But we would like to see that we act in such a manner that nobody should point an accusing finger towards us that since the Government in Uttar Pradesh belonged to another party, we are very quick in taking action against them. That kind of allegation should not be there against us. We should have enough material on our records to show that in spite of all the efforts, reasonable efforts, there has been no positive response. Even the court order is also being violated. If that be the situation, certainly. I can assure the House that the Government wil lnot release to act.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.30 P.M. for lunch.

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-eight minutes past two of the clock, [The Vice-Chairman (Shrimati Sushma Swaraj) in the Chair.]

Resolution re.starvation deaths in tribal areas of Tripura

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अब श्रीमती सरला माहेश्वरी के निम्नलिखित संकल्प पर विचार किया जाएगा --

"यह सभा भुखमरी और भूख से संबंधित रोगों के कारण त्रिपुरा में आदि-, वासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हुई मौतों समाचारपत्रों की रिपोर्टों के अनुसार जिनकी संख्या 400 से भी अधिक है, पर अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह स्थिति की गंभीरता को समझे और प्रभावित आदिवासी लोगों को तत्काल राहत पहुंचाए और साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करे कि —

i. इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मार्फत सप्लाई की जा रही वस्तुओं की मात्रा दुगुनी की जाए,

ii. व्यापक स्तर पर ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू की जाएं, और

iii. भूख से संबंधित रोगों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सा राहत उपाय शुरु किए जाएं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं बहुत ही दुख और गहरे शोक के साथ आज यह संकल्प इस सदन में उपस्थित कर रही हूं।

महोदया, ऐसा लगता है कि जैसे हवा में फिर औपनिवेशिक शासन के भूख और मौत के काले साये मंडराने लगे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरे हाथ में सूची है जिसमें....

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सरला माहेश्वरी जी, आप पहले अपना संकल्प उपस्थित कीजिए....

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, मैंने समझा था कि आपने संकल्प पढ़ दिया है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा...

उपसभापति (श्रीमति सुषमा स्वराज) : नियम यही है कि आप पहले अपना संकल्प पढ़िए फिर भाषण करिए...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करती हूं :

"यह सभा भुखमरी और भूख से संबंधित रोगों के कारण त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हुई मौतों, समाचारपत्रों की रिपोर्टों के अनुसार जितकी संख्या 400 से भी अधिक है, पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह स्थिति की गम्भीरता को समझे और प्रभावित आदिवासी लोगों को तत्काल राहत पहुंचाए और साथ-साथ भी सुनिश्चित करे कि —

(1) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मार्फत सप्लाई की जा रही वस्तुओं की मात्रा दुगुनी की जाये,

(2) व्यापक स्तर पर ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू की जाएं, और

(3) भूख से संबंधित रोगों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सा राहत उपाय शुरु किये जायें"

उपसभाध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने पहले कहा मैं बहुत ही दुख और क्षोभ के साथ आज यह प्रस्ताव इस सदन के समक्ष उपस्थित कर रही हूं। ऐसा लगता है कि हवा में फिर औपनिवेशिक युग के भूख और मौत के काले साय मंडराने लगे हैं। मेरे हाथ में एक सूची है अगर आप चाहें तो मैं आपकी जानकारी के लिए सदन और सरकार की जानकारी के लिए यहां रख सकती हूं। इस सूची में 401 लोगों के नाम दर्ज हैं। नाम, पते और दिनांक कि कब-कब इनकी मौते हुई हैं। इनकी मौत भूख की मार से, अनाज के अभाव में हुई है। आज के युग में भूख और भूख जनित मौतों की यह दर्दनाक दास्तान सुनकर रूह कांपती है। लगता है कि जैसे कोई अशुभ दानवी शक्ति ने हमें पांच दशक के पहले के इतिहास में धकेल दिया हो। जब बंगाल के महाकाल, जिसे मनवन्तर कहा जाता था, में लाखों लोग इस तरह मर गये जिस तरह पड़ से सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, उस महाकाल को देखकर बंगाल के सुप्रसिद्ध विद्रोही कवि सुकांत ने लिखा था :

सुन रे मालिक सुन रे जमींदार...

तोदेर प्रासादे जमा होलो कोतो मृत
मानुषेर हाड़ हिसेब की दिबी तार

अर्थात् हे जमींदार, हे मालिक तुम्हार महल में कितने मृत लोगों की अस्थियां जमा हुयीं हैं? क्या है उसका हिसाब दोगे? उस कवि ने इस दर्दनाक मौत के खिलाफ अपने संकल्प का इजहार करते हुए कहा था :

हिंस मानवितार जदि आमी केऊ होई आदिम.........

स्वजन हारानो शमशानें, तोदेर चिता आमी तुलबोई

श्रीमती सरला माहेश्वरी

अर्थात् यदि, मुझमें आदिम हिंसा का जरा भी अवशेष है, तो श्मशान में मैंने अपने आत्मीय लोगों को खोया है, उस श्मशान में तुम्हारी चिता भी अवश्य ही उठाऊंगा । उपसभाध्यक्ष महोदया, त्रिपुरा की स्थिति भी मुझे भयावह दिनों की याद दिलाती है। आज के युग में जब हम एक ओर 21 वीं सदी में जान की बातें कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की बातें कर रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह की दर्दनाक मौतें निश्चित रूप में हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देती है।

यह सच है कि देश के अन्य भागों से भी अकाल और अन्नाभाव की खबरें आ रहीं हैं और 15 जुलाई के नवभारत टाइम्स के प्रथम पृष्ठ की यह खबर है, एक रिपोर्ट छपी है, जिसका शीर्षक है : "अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लोग दाने-दाने को मोहताज ।" इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि महाराष्ट्र के 26 जिलों के 3 करोड़ लोग सूखे और अकाल से प्रभावित हैं। 20 हजार गांव में पीने के पानी का अभाव है। गुजरात के कुल 18,246 यानी 62 परसेंट गांव सूखा प्रभावित घोषित किये गये हैं । मध्य प्रदेश के सवा करोड़ लोग अकाल के साये में हैं।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, एक मिनट। अच्छा हुआ अहलुवालिया जी तशरीफ ले आयें । इस गम्भीर विषय पर गैर सरकारी प्रस्ताव है, भूख और भुखमरी और त्रिपुरा के ट्राइबल लोगों के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन सरकारी पक्ष का एक भी सदस्य सदन में नहीं है। यहां तक कि त्रिपुरा के निर्वाचित जो सदस्य हैं, वे भी नहीं हैं (व्यवधान)

†[شری محمد سلیم: مانئیہ اپ سبھا ادھیکش مہودیہ - ایک منٹ. اچھا ہوا آہلووالیہ جی تشریف لے آئے. اس گمبھیر وشے پر غیر سرکاری پرستاؤ ہے. بھوک اور بھکمری اور تریپورہ کے ٹرائبل لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. لیکن سرکاری پکش کا ایک بھی سدسیہ سدن میں نہیں ہے یہاں تک کہ نرواچت جو سدسیہ ہیں وہ بھی نہیں ہیں ... "مداخلت"...]

उपसभाध्यक्ष : (श्रीमती सुषमा स्वराज) मंत्री जी बैठे हैं।

श्री मोहम्मद सलीम : अहलुवालिया जी बंगाल की हवा थोड़ी आप में है । (व्यवधान) ।

†[شری محمد سلیم: آہلووالیہ جی بنگال کی ہوا تھوڑی آپ میں ہے ... "مداخلت"...]

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मंत्री जी बैठे हुए हैं और सत्ता पक्ष के लोग आ रहे हैं। अहलुवालिया साहब स्वयं बोलने वाले हैं। (व्यवधान)

मंत्री जी बैठे हुए हैं और सत्ता पक्ष के लोग आ रहे हैं । अहलुवालिया जी केवल सुनने ही नहीं आये हैं, सुनाने भी आये हैं । वे बोलने वाले हैं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं चाहती हूं कि सत्ता पक्ष के लोगों की इसमें भागेदारी होती और वे इस बात को समझ पाते कि त्रिपुरा में जैसी सरकार चल रही है और उनकी पार्टी की सरकार चल रही है, वहां की स्थिति को वे खुद दूसरी के मुंह में से सुनते तो शायद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी ज्ञान प्राप्त होता उससे कुछ कदम उठाये जाते । हम इस जनतंत्र के बड़े सदन में बैठ कर बहस

†[ ] Transleteration in Arabic script.

कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अहम बात यह है कि समाज में अगर मूल्यों में गिरावट शुरू होती है तो हर स्तर पर होती है। हम भी उससे अछूते नहीं हैं।

जैसा मैं बता रही थी कि "20 हजार लोग पीने के पानी के अभाव में पीड़ित हैं। गुजरात में कुल 18,246 यानी 62 प्रतिशत गांव सूखे से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में सवा करोड़ लोग अकाल के साये में हैं और राजस्थान में 70 हजार गांवों में कोई 50 हजार लोग भूख और अकाल झेल रहे हैं।" इससे लगता है कि अकाल और सूखा किसी क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं है बल्कि यह आज हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों की ज्वलन्त समस्या बन चुकी है। इन तमाम समस्याओं की तह में जाकर आप देखेंगे तो जिस एक समस्या को आप समान रूप से पाएंगे जिसने इन तमाम क्षेत्रों को एक सूत्र में पिरो दिया है, वह सूत्र यह है कि इन समान जगहों में चाहे वे सूखे से पीड़ित हों, चाहे अकाल से पीड़ित हों, चाहे अन्नाभाव से पीड़ित हों, पीड़ित लोग आदिवासी समाज के और अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोग हैं। मध्य प्रदेश में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी जंगलों में कंद मूल और जड़ खा कर जी रहे हैं। आदिवासी बड़े पैमाने पर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह समाज का सबसे कटु यथार्थ है कि विपदा चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव द्वारा निर्मित उसकी करारी चोट हमेशा समाज के निम्नतम हिस्से पर ही पड़ती है।

लेकिन इस मामले में चूंकि मैंने त्रिपुरा का सवाल उठाया है और जब त्रिपुरा का सवाल मैं उठाती हूं तो निश्चित रूप से त्रिपुरा को इन तमाम चीजों से अलगाते हुए त्रिपुरा की जो खास स्थिति है उस खास स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। त्रिपुरा की खास विशेषता यह है कि वहां के आदिवासी और अनुसूचित और जन जाति के लोग सिर्फ अकाल और सूखे से पीड़ित नहीं हैं बल्कि त्रिपुरा के आदिवासी राज्य के द्वारा संगठित और सुनियोजित रूप में चलाई जा रही हिंसा और विद्वेष की भावनाओं के द्वारा शोषित और अत्याचारित भी हो रहे हैं। वहां के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भूख और मौत के काले साये मंडरा रहे हैं। पिछले नवम्बर और दिसम्बर महीने में त्रिपुरा के ही नहीं, हिन्दुस्तान के तमाम अखबारों में ये सब रिपोर्टें छपी हैं जिनमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से वहां की आदिवासी महिलायें, बच्चे, बूढ़े भूख के कारण मर रहे हैं। वहां महामारी और बीमारियां, जैसे रक्त पेचिश, मलेरिया और कौलरा से ग्रस्त लोग तिल-तिल कर मर रहे हैं। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है। एक ओर जहां भूख से लोग मर रहे हैं, महामारियों से मर रहे हैं, वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको आश्चर्य होगा, इस जनतंत्र में एक ऐसी सरकार वहां पर कायम है जिस सरकार के शासन के तले आदिवासी भूख से मर रहे हैं। इस पर ध्यान न देकर वहां की सरकार संगठित रूप से सुनियोजित रूप में आदिवासियों के विरुद्ध दमनकारी कानूनों का इस्तेमाल कर रही है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं, उपसभाध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने पहले ही कहा विपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, उसका सामना निम्न वर्ग को ही करना पड़ता है। आज जो त्रिपुरा की हालत है, एक तरफ तो उनकी जूम की खेती दो-दो बार बरबाद हो चुकी है, इस प्राकृतिक विपदा से वे लड़ ही रहे हैं और दूसरी तरफ त्रिपुरा सरकार किस तरह इस भूख से मारे जा रहे आदिवासियों के प्रति रुख अपना रही है, इसको सोचकर मानवता की रूह कांप जाती है। उपसभाध्यक्ष महोदया, पिछली फरवरी महीने में ही अखबारों में खबर आयी है कि त्रिपुरा की गठजोड़ सरकार एक संकट में पड़ गयी।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी तो इसलिये बैठे हैं कि उनको जबाब देना है। अहलुवालिया जी इसलिये बैठे हैं कि उन्हें इनके तुरन्त बाद बोलना है। बोलने के बाद ये भी चले जायेंगे। इसलिये नोट किया जाय कि कोई भी मेंबर . . .
(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): आप परेशान क्यों हैं? . .

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : पूर्वानुमान क्यों लगा रहे हैं कि चले जायेंगे . .

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह पूर्वानुमान का सवाल नहीं है। यह विडंबना है हमारे जनतंत्र की . . (**व्यवधान**) . . .

उपसभाध्यक्ष, (श्रीमती सुषमा स्वराज) यह गंभीर विषय है, इसको आप जारी रखें ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : व्यंग बना दिया है सत्ता पद के लोगों ने । इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात हो रही है लेकिन सत्ता पक्ष के लोग नहीं हैं । त्रिपुरा के पूर्व मुख्य मंत्री हमारे सदन के सदस्य हैं । उन्हें तो यहां रहना चाहिए था । जब उन्हें यहां अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं है तो वहां पर क्या जिम्मेदारी का अहसास करेंगे । . . (**व्यवधान**) . .

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अहलूवालिया जी, आप अपने समय पर बोलिए । मैं गौतम जी से भी कहूंगी कि वह बहुत गंभीर विषय है इसमें व्यवधान न डालें तो अच्छा हो । वे बहुत दर्द के साथ अपनी बात रख रही हैं । रखिए आप ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : पिछले फरवरी के महीने में त्रिपुरा में सरकार का यह गठजोड़ संकट के भंवर में फंस गया था । इसके मूल में भी वही बात थी । त्रिपुरा की जो गठजोड़ सरकार थी, उसका एक बड़ा घटक, कांग्रेस, जिस तरह से आदिवासियों और बहुसंख्यकों के बीच में विद्वेष का वातावरण पैदा कर रहा था, एक तरफ तो वे अंध राष्ट्रवाद की हवा दे रहे थे और दूसरी तरफ आदिवासियों के विरुद्ध दमनमूलक कानूनों का इस्तेमाल करके यहां तक कि आदिवासियों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे थे । इसलिए आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले टी०यू०जे०एस०के लिए यह संभव नहीं रहा कि वह और इस सरकार का घटक बनकर रह सकता । इसलिए उसने घोषणा कर दी कि अब वह इस सरकार में शामिल नहीं रहेगा और उसने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी । लेकिन इसके बावजूद उपसभाध्यक्ष महोदया, आप भी कांग्रेस की राजनीति से परिचित हैं कि किस प्रकार खरीद-फरोख्त की राजनीति करते हैं और फिर उन्होंने अपनी सरकार वहां पर कायम कर ली । सुधीर रंजन मजूमदार जो वहां के मुख्य मंत्री थे, उनको बलि का बकरा बना कर यहां राज्य सभा में तोहफे के तौर पर भेज दिया गया और गृह मंत्री समीर रंजन वर्मन को वहां का मुख्य मंत्री बना दिया गया । लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदया, सवाल यह है कि क्या मुख्य मंत्री बदलने से त्रिपुरा की समस्या बदल गई है, क्या वहां के दृश्य बदल गये हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले हैं । आज वहां के हालात से पहले से भी कहीं बदतर हैं । उपसभाध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि त्रिपुरा की स्थिति लगातार बद से बदतर होती आ रही है । मेरे पास अखबारों की कतरनें हैं । आप चाहें तो मैं तमाम अखबार आपको दिखा सकती हूं लेकिन मैं इतना संसद का समय नहीं लूंगी । ये तमाम अखबार त्रिपुरा से निकलते हैं । इन अखबारों को आप उठाकर देखिये, एक भी दिन ऐसा नहीं मिलेगा जिस दिन भूख से एक आदिवासी की मौत न हुई हो, जिस दिन एक परिवार के किसी न किसी व्यक्ति की मौत न हुई हो । महोदया, मैं कुछ घटनाओं का हवाला देना चाहूंगी । 5 जून के अखबार की खबर है कि "4 के जी चाले विनिमये संतान" "चार किलो चावल के बदले में संतान की बिक्री" यह खबर त्रिपुरा छामनी इलाके की है । अखबार में आगे कहा गया है कि भूख की आग से संतान की बिक्री इस बार रुपए की एवज में नहीं, सिर्फ चार किलो चावल के बदले में मां ने पड़ोसी को अपना एक वर्ष का बच्चा सौंप दिया । उपसभाध्यक्ष महोदया, यह घटना अकाल-पीड़ित छामुनी ब्लाक के पश्चिम गोविन्द बाड़ी गांव सभा के कालछड़ा में पिछली 21 मई को घटी थी । उल्लेखनीय है कि महुपाड़े के मुहुरम रियांग पाड़े में प्रदीप देव वर्मा ने अभाव के चलते 80 रुपए में अपने दो बच्चों को बेचा था ।

संसदीय प्रतिनिधियों के एक दल की यात्रा के समय यह तथ्य सामने आया था।

27 जून के अखबार की एक खबर का शीर्षक है–"परीबाला अब फिर भात नहीं मांगेगी–और 6 प्राणी मर गये" यानी परीबाला अब फिर चावल नहीं मांगेगी। खबर में यह बताया गया है कि 20 जून को महारानीपुर के लक्ष्मचंद्रपाड़ा में 30 वर्ष की एक आदिवासी युवा वधू परीबाला ने भूख से दम तोड़ दिया। तीन दिन पहले बेरोजगार पति सुधीर देव बचने का कोई और उपाय न देख कर जंगल से लकड़ी काटने के लिए चला गया। जंगल से लकड़ी काट कर तीन चार रुपए जो उसे मिले उससे वह चावल खरीद कर लाया। इससे पहले कि वह चावल अपनी भूखी पत्नी के मुंह में दे पाता जब वह घर में आया तो उसकी पत्नी लुढ़की पड़ी थी यानी मर चुकी थी। इसी खबर में उत्तर महारानीपुर तथा उससे संलग्न कूच कालोनी में हाल ही में भूख से तड़प कर मरने वाले छः लोगों की सूची छपी है जिसमें 45–50 वर्ष के प्रौढ़ों सहित पांच वर्ष के नन्हे बच्चे भी शामिल हैं। 28 जून को कूच कालोनी के भूखे लोगों को मौत से बचाने के लिए उन्हें तत्काल राहत पहुंचाने के लिए त्रिपुरा के विधायकों का एक दल वहां के पूर्व मुख्य मंत्री नृपेन चक्रवर्ती के नेतृत्व में जिला मजिस्ट्रेट से मिला था और उन्हें डेढ़ सौ लोगों की एक सूची दी थी जिनके घर में एक वक्त के लिए खाने का एक दाना भी नहीं था। 29 जून की यह खबर है कि धर्मनगर महकमे के राजनगर गांव में लगातार भूखे रहने के कारण 45 वर्षीय धीरेन्द्र देवनाथ और उसकी पत्नी अनन्तमणि देवनाथ को 20 जून को अपनी जान गंवानी पड़ी। वे अपने पीछे भूख से मरने के लिए 8 वर्ष का बेटा और पांच वर्ष की बेटी छोड़ गये हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, यह है त्रिपुरा के आदिवासी समाज के बड़े हिस्से की स्थिति और राज्य सरकार का उनके प्रति रुख क्या है? राज्य सरकार उन्हें राहत देने के बजाय उन पर ज्यादा से ज्यादा सख्ती कर रही है। हाल ही में त्रिपुरा की सरकार ने एक फरमान जारी किया। तमाम फारेस्ट अधिकारियों को बुला कर के उन्होंने एक नया शुल्क लगाने की घोषणा की है जिस पर एक जून से अमल भी शुरू हो गया है। आदिवासी जिनकी आय का मूल स्रोत जंगलों से लकड़ी बीन कर लाना है और कंदमूल लाना है जिसकी बिक्री कर के वे पांच छः रुपए रोज कमाते हैं। अब एक बंडल जलावन लकड़ी जिसकी बिक्री पर उसको पांच छः रुपए मिलते हैं उस पर पहले एक रुपए सरकार को देना पड़ेगा। इससे पहले कोई शुल्क नहीं लगता था। जो लकड़ी का बंडल रिक्शा पर ढो कर लाएगा उस पर पांच रुपए लगेगा और जो कंधे पर ढो कर आएगा उस पर दो रुपया लगेगा। उपसभाध्यक्ष महोदया, आश्चर्य होता है कि जो लोग भूख से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, उन भूख और बीमारी से मर रहे लोगों को सहलाने और मरहम लगाने की जगह सरकार उनके घावों पर नमक छिड़क रही है। आर्थिक संकट की बात की जा रही है। अगर आर्थिक संकट है तो क्या कारण है कि त्रिपुरा में आज तक इतना बड़ा मंत्रिमंडल नहीं बना जितना आज है। समीर रंजन बर्मन के नेतृत्व में तमाम विधायक दो तीन विधायकों को छोड़ कर सारे के सारे विधायक मंत्री बन गये हैं। इतना बड़ा मंत्रिमंडल उन्होंने बनाया है। जनता का पैसा मंत्रियों पर खर्च करने के लिए है लेकिन भूख से मरते आदिवासियों के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है। हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। आदिवासियों की आमदनी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ऐसे कठोर कानून लगा रही है और दूसरी तरफ ऐयाशी के लिए मंत्रियों पर आलतु-फालतू खर्च करती जा रही है। पिछली 9 जून की एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगी कि किस तरए से त्रिपुरा की सरकार इन आदिवासियों पर जुल्म कर रही है। आदिवासियों की एक

3.30 P.M कालोनी में 9 जून को जहां कि भूख का आलम था, जहां बीमारी और मौत के काले साये मंडरा रहे थे वहां त्रिपुरा की सरकार ने पुलिस भेजी और उस कालोनी में गोलियां चलाईं जिसके चलते एक 30 वर्षीय युवती सुगमत देव वर्मा की

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

हत्या कर दी गयी। त्रिपुरा विधान सभा में विपक्ष के नेता दशरथ देव ने 20 जून को प्रधान मंत्री के नाम एक खत लिखा है। मैं उस खत को यहां पर पढ़ना चाहूंगी। अपने पत्र में श्री देव ने कहा है कि आज जब त्रिपुरा के अल्पसंख्यक आदिवासी अकाल की मार को झेल रहे हैं उसी समय वहां की समीर रंजन की मोर्चा सरकार ने उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। सिर्फ भूख के कारण अब तक अनुमानतः 500 आदिवासी जुमिया अपने प्राण गंवा चुके हैं। अकेले छामनू ब्लाक के 330 लोगों के भूख से मरने के रिकार्ड दर्ज हैं। उन अकालपीड़ित क्षेत्र के लोगों को दुगना राशन और ग्रामीण रोजगार प्रकल्पों के जरिये राहत पहुंचाने के बजाय समीर रंजन बर्मन की सरकार उग्रपंथियों से लड़ने के नाम पर आदिवासियों के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लड़ाने पर मुब्तिला है। कुछ उग्रपंथी संगठनों को वहां की राज्य सरकार ही हथियार दे रही है। अपने इसी पत्र में श्री देव ने त्रिपुरा में लगातार चल रहे बंगलादेश से अनुप्रवेश का भी उल्लेख किया है। उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा है कि पिछले साढ़े चार साल में 3 लाख से भी अधिक बंगला देश अनुप्रवेशकारियों ने विभिन्न भ्रष्ट तरीकों से भारत की नागरिकता भी ले ली है। स्वशासी जिला परिषदों में भी उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। इसके चलते आदिवासियों और बंगाली समाज के बीच भयावह तनाव पैदा हो रहा है। अपने इस पत्र के अंत में श्री दशरथ देव ने केन्द्रीय सरकार से अभावग्रस्त आदिवासियों के लिए तत्काल बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने की मांग की है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि त्रिपुरा का नाम वहां के एक आदिवासी समुदाय "ट्रिपिरा" के नाम पर पड़ा। आजादी के पहले जहां इन "टिपिरा" आदिवासियों की आबादी 70 प्रतिशत थी आज आजादी के बाद ये आदिवासी अपनी ही मातृभूमि में बेगाने हो गये हैं। आज मूल आबादी में उनका हिस्सा एक चौथाई रह गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहूंगी कि आज यह सच है कि देश के अनेक भागों से अकाल और अभाव के समाचार आ रहे हैं लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि त्रिपुरा की स्थिति अलग है और त्रिपुरा की स्थिति की यह भयावहता हम अपने देश के समग्र आदिवासियों की स्थिति के संदर्भ में देखें।

महोदया, आदिवासी अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की 29वीं रिपोर्ट का मैं यहां पर हवाला देना चाहूंगी। महोदया, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इज्जत की जिंदगी जीने के लिए वाजिब व्यवस्था और उपयुक्त वातावरण के मामले में हमारे देश में आज की हालत बड़ी ही चिंताजनक है। हमारी व्यवस्था में ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। एक ओर आधुनिक संगठित क्षेत्रों में निश्चिन्तता का माहोल है तो दूसरी ओर परम्परागत असंगठित क्षेत्र में साधारण आदमी के लिए सवाल है दो जून की रोटी का। इस क्षेत्र में भी जो साधन सम्पन्न और समझदार हैं वे यही चाहते हैं कि किसी तरह आधुनिक क्षेत्र में पहुंच जाएं। इस क्षेत्र में पूरा आलम छीना झपटी का है, साधारण लोगों के पास जो कुछ भी बचा है वह भी कानून, ताकत और पैसे के बल पर छिनता चला जा रहा है। यदि इधर छिनता चला जा रहा है तो वह उधर जमा होता चला जा रहा है। इस तरह से हमारे देश में दोहरी ही नहीं तिहरी व्यवस्था कायम होती जा रही है, इंडिया, भारत और हिंदुस्तनवा। अधिकतर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इसी हिंदुस्तनवा की आखिरी मंजिल में शामिल हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, इसी रिपोर्ट में आगे एक और टिप्पणी की गई है।

"जब विकास की अवधारणा में हमने पश्चिमी देशों के विकास का रास्ता आदर्श मान लिया है। इसी सोच में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि पहली और दूसरी दुनिया के विकास के लिए तीसरी दुनिया का कूड़ेदान बनाना जरुरी था। उसी सिलसिले में तीसरी दुनिया के लिए चौथी दुनिया का कूड़ेदान चाहिए। आज हमारे

देश में हिंदुस्तानवा बड़ी कूड़ादान बन गया है ।"

आयुक्त ब्रह्मदेव की यह टिप्पणी बड़ी कड़वी है, लेकिन टिप्पणी भले ही कड़वी हो, बात भले ही कड़वी हो, लेकिन यही यथार्थ है, यही हमारे समाज की सच्चाई है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आज त्रिपुरा में जो भयावह हालात हैं, इनको देखते हुए अगर त्रिपुरा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रह सकती है और हमारी केन्द्रीय सरकार भी तमाम रिपोर्टस से आंखें चुरा कर, संसद में हो रही बहस से आंखें चुरा कर बैठी रहना चाहती है, तो उपसभाध्यक्ष जी, मानवता हमें कभी माफ नहीं करेगी ।

इसलिए मैं चाहती हूं कि आज हमारे इस सदन में और मैं मंत्री महोदय से भी अपील करूंगी कि चाहे किसी भी राजनीतिक विचारों से हम संबद्ध क्यों न हों, लेकिन जहां मानवता का सवाल आता है, इनसानियत का सवाल आता है, वहां मानवता और इनसानियत के पक्ष में मैं यह चाहूंगी कि मेरे संकल्प को वे स्वीकार करें और मैं यह मांग करना चाहूंगी कि त्रिपुरा में छांगनू गड़ा, कंचनपुर तथा आठारमूड़ा पहाड़ी अंचल के हिस्सों को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाए ।

जब तक आदिवासी जुमिया परिवारों की जूम की अगली फसल नहीं मिलती तब तक सस्ती दरों पर इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को दुगना राशन दिया जाए ।

जवाहर रोजगार योजना, एस०आर० इ०पी० तथा अन्य इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं के जरिए उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए ।

तत्काल दूर-दराज के क्षेत्रों में राशन की दुकानों में राशन का पर्याप्त भंडार दिया जाए ताकि बारिश के माहौल में राशन की अनुपलब्धता का बहाना बना कर उन्हें राशन से वंचित न किया जाए।

भूख जनित बीमारियों, मसलन रक्त पेचिश और हैजा की तरह की महामारियों से बचने के लिए सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किये जायें। उन सभी क्षेत्रों में पीने के पानी की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए और चिकित्सा दलों को तत्काल भेजा जाना चाहिए। भूख से जान गंवाने वालों अथवा भूख-जनित बीमारियों से पीड़ित परिवारों को तत्काल रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

अपने तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, उपसभाध्यक्षजी, मैं चाहूंगी कि इस सदन, और विपक्ष के लोग ही नहीं, बल्कि सरकारी पक्ष के लोग भी इस संकल्प को अनदेखा न करें क्योंकि जब जुल्म और अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वह फिर विस्फोट के रूप में फट पड़ता है और यही जुल्म और अत्याचार वह कच्ची जमीन तैयार करते हैं जहां उग्रवाद फलता-फूलता है।

इसलिए मैं अपने सरकारी पक्ष के लोगों से निवेदन करूंगी कि वे उग्रवाद के फैलाने और पनपने का रास्ता तैयार न करें। हमारे देश की एकता और अखंडता से न खेलें। **(समय की घंटी)** इस तरह की राजनीति करके बंगाली समाज, आदिवासी समाज में फूट डालने की राजनीति न करें। औपनिवेशिक साम्राज्यवादियों ने फूट डालो और राज करने की जो नीति अपनाई थी, उपसभाध्यक्ष जी, आज त्रिपुरा का शासक वर्ग खास करके कांग्रेस (ई०) आज वहां पर फूट डालो और शासन करो की वही पुरानी नीति अपना रही है।

इसलिए मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों से निवदन करना चाहूंगी कि इस तरह की दोहरी नीति को बंद करें आज जब आप हिंदुस्तान की राजनीति को चला रहे हैं तो बड़ा दायित्व है आप पर। जब ऐसे ही देश की एकता और अखंडता के सामने इतने बड़े खतरे हैं, तब छोटी-छोटी तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के चलते यह घिनौना खेल न खेलें।

इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, आखिर में मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि इस संकल्प पर बहस हो और बहस के बाद इस संकल्प को स्वीकृत किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपका धन्यवाद करना चाहती हूं।

The question was proposed.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं श्रीमती सरला

[सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया]

माहेश्वरी जी द्वारा प्रस्तावित संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उनके भावुकता से भरे शब्दों को सुनकर मैं भी भावुक हो गया और भावुक होते-होते मुझे महसूस होने लगा कि शायद मैं सदन में श्री शरद चन्द्र जी के किसी उपन्यास को सुन रहा हूं या प्रेमचन्द जी के किसी उपन्यास को जोकि उन्होंने गरीबी, बेकारी और भुखमरी पर लिखा था। उपाध्यक्ष महोदया, भावुकता के भाषण तो बहुत दिए जा सकते हैं, किन्तु राजनीति से प्रेरित होकर जब भावुकता आती है तो उससे सत्ता की लोलुपता की बू आने लगती है। माननीय सदस्या गरीबी और भुखमरी को जिस तरह से पेश कर रही थीं, उससे महसूस हो रहा था कि शायद इसका जन्म सन् 1987 के बाद ही हुआ है और इसके पहले तो यह देश में और त्रिपुरा में नहीं थी। महोदया, मैं सत्ता पक्ष में बैठकर भी यह महसूस करता हूं कि गरीबी उस वक्त से चली आ रही है जबसे इंसान पैदा हुआ है और मेरा तो ख्याल है कि भुखमरी भी उस वक्त से इंसान से जुड़ी हुई है जबसे कि इंसान के शरीर के साथ पेट जुड़ा हुआ है, भूख जुड़ी हुई है और जिंदगी में अभाव भी तभी से जुड़े हुए हैं जबसे कि हमें हमारा पेट भरने के लिए या हमारे बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, गुजर-बसर करने के लिए चीजों की जरूरत पड़ी है। तो अभाव होता ही है, लेकिन इसे राजनीति से प्रेरित होकर तोड़-मरोड़कर पेश करना, अच्छा नहीं है क्योंकि सन् 87 से पहले 10 साल तक उस राज्य में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य था। आज जो बच्चा वहां पर 13 साल का है या 15 साल का है, वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पहले साल में पैदा हुआ था। पिछले 10 सालों में उसकी परवरिश कैसे हुई, इसे भी जानने की जरूरत है कि उन 10 सालों में बच्चे को उसकी मां का दूध मिला था या नहीं मिला? पाठशाला में जाने के लिए उसके पास किताबें और स्लेट थी या नहीं थी, यह भी विचार करने योग्य है, पर भावुकता में बहकर हम किसी एक पर्टीकुलर राजनीतिक दल पर आघात करें, तो वह बड़े शर्म की बात है। माननीय सदस्या, अगर उनके प्रस्ताव में जो कुछ लिखा है, वही पढ़तीं और वही सुनातीं तो मेरा नजरिया कुछ और होता, पर उन्होंने तो बात लादो सुधीर रंजन मजूमदार की सरकार की, समीर बर्मन की सरकार की। महोदया, सरकारें तो आती और जाती रहेंगी, पर इन गरीबों का फैसला कौन करेगा? इन गरीबों की भूख को कौन शांत करेगा? उस भूख को मिटाने के लिए इन्हीं की पार्टी की सरकार कहती है कि हमें कास्टलैस सोसायटी, क्लासलैस सोसायटी चाहिए, हमें ओवर आल एकोनोमिक डवलपमेंट की जरूरत है, तो क्या कर रही थी आपकी सरकार 10 साल वहां? क्या एकोनोमिक डवलपमेंट किया आपने उस राज्य का? क्यों नहीं रोका जब वहां 12 हजार टन से लेकर 15 हजार टन गेहूं जा रहा था या चावल जा रहा था और जब 10-10 हजार टन बंगलादेश को स्मगल हो रहा था? क्यों नहीं आपके वालिंटियर्स ने रोका और अब रोका तो आपने विरोध किया, हड़तालें कीं, बंद कर दिए। क्यों स्मगलर्स को पकड़ा, यह क्यों नहीं प्रस्ताव में लिखा? . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री **मोहम्मद सलीम** : इसका इससे क्या है ? . . . (**व्यवधान**) . . .

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): सलीम जी, आपको बोलना है भाई। बीच में व्यवधान न करें।

श्री **सत्य प्रकाश मालवीय** (उत्तर प्रदेश) : यह जो आप बोल रहे हैं, प्रस्ताव में संशोधन दे दीजिए। . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Whether it is correct or not, let him speak.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): We will also be responding. *(Interruptions)*

SHRI MD. SALIM: Today he is not prepared. I respect him for his prepared speeches.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I can always speak unprepared. Don't worry.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): बोलिए, बोलिए, अहलुवालिया जी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाया ? और, आज जो आप उठा रहे हैं कि वहां की पापुलेशन के हिसाब से राशन कार्ड, तो कभी आपने देखा आंकड़ों को कि वहां जो पापुलेशन है उससे कहीं ज्यादा वहां राशन कार्ड हैं, एक्सेस राशन-कार्ड बने हुए हैं और राशन-कार्ड की फुलफिल के लिए वहां पर ज्यादा राशन भी दिया जाता है। पर, जो बांगला देश के बोर्डर पर स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए आपने आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

महोदया, आपने अखबारों का हवाला दिया। मैं भी अखबारों का हवाला दे सकता हूं। यह "हिंदुस्तान टाइम्स" की रिपोर्ट है। अगर अखबारों के हवाले पर ही हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, तो अखबारों ने ही यह लिखा हुआ है। इसके बावजूद वहां पर भुखमरी फैली है, तो क्या वाकई उसके साथ जोड़ती है या वहां आंत्रशोध है, हैजा है या और सब कुछ है ? वाकई बात यह है कि हां, वहां बेकारी है। उसका कारण है कि वहां जितने राजसत्ता करने वाले, राज चलाने वाले आए, चाहे कांग्रेस के हों या सी.पी.एम. के हों, कोई बड़ी इन्डस्ट्री वहां नहीं लगी। बेकारी है वहां। वहां के गरीब लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। वहां का गरीब ट्राइबल आदमी जंगल का रहने वाला है, वनवासी है, उसकी अपनी कोई परचेजिंग पावर नहीं है और उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए आपने क्या कोई उपाय किए ? चलिए, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि हम चूक गए, लेकिन आपने तो दस साल राज किया, आपने क्या किया ? आपने कुछ नहीं किया। यह दोषारोप क्यों है ? हम सब जिम्मेदार हैं। पर, वहां जिस तरह से इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है कि चार सौ आदमियों की स्टार्वेशन डेथ हुई (**व्यवधान**)

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Did you hear of starvation deaths during those days?

SHRI S. S. AHLUWALIA: I will come to that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Please do not interrupt. Speak only with the permission of the Chair.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदया, इस राज्य से भुखमरी से लोग मरे हैं, उनकी संख्या तो जो है, उसके बावजूद वहां बेकारी के कारण काफी माइग्रेशन होता है और हमारे देश के आदिवासी लोग बांगला देश चले जाते हैं, हमारे त्रिपुरा राज्य के आदिवासी लोग रोटी की, कपड़े की, रोजगार की खोज में असम चले जाते हैं और मिजोरम चले जाते हैं। पर नौकरी कहां ? नौकरियां कहां मिल रही हैं ? क्योंकि हर राज्य में बेकारी है, भुखमरी है।

हम तो आर्गेनाइज्ड विलेज जो हैं वहां के लोगों की परचेजिंग कपेसिटी नहीं बढ़ा सके तो अनआर्गेनाइड विलेजेज में कहां पहुंच सकते हैं फ्रूट गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ने वहां पहुंचाना है। किन्तु उसका यह तरीका नहीं है कि हम एक दूसरे पर दोषारोप करें और यह दोषारोप करके एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करें। उसके लिए पालिसी बनी है। अभी-अभी, वैसे मेंशन नहीं करना चाहिए फिर भी मैं कहता हूं, मैं उस सदन की गैलरी में बैठा सुन रहा था, प्रधान मंत्री जी बता रहे थे इस बार रूरल डवलमेंट में एट्थ फाइव ईयर प्लेन में 14 हजार करोड़ का जो प्रावधान था उसको बढ़ाकर 30 हजार करोड़ का प्रावधान लगाया जा रहा है। यह जो लगाया जा रहा है, उसमें प्राइरिटि एरिया में ट्राइबल एरिया आता है और उस ट्राइबल एरिया में यह जो स्थिति है, जहां पर ट्राइबल पापुलेशन है, उसमें त्रिपुरा भी एक है और उसमें त्रिपुरा का भी ख्याल किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

है पर अगर इन चीजों को रोकना है और अगर कोई यह सोचे कि सत्ता पक्ष अकेले उसे रोक सकता है तो यह असंभव है। अगर कोई यह सोचे कि मैं ही कस्टोडियन हूं विपक्ष में बैठा हूं मैं ही सिर्फ एक धर्मात्मा हूं मैं ही गरीबी हटा सकता हूं या मैं ही गरीबों को नौकरी दिला सकता हूं या बेकारी दूर कर सकता हूं तो यह भी भ्रम है। क्योंकि जब भी आपको देश में गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है तो देश के जितने राजनीतिक दल हैं उनको इकट्ठे खड़े होकर एक पोलिसी को स्वरूप देना पड़ेगा और पौलिसी खड़ी करके उसको रुपायन करना पड़ेगा। जब तक वह पौलिसी सिर्फ कागजों में लिखी हुई है यह बड़े-बड़े बहीखातों में लिखी हुई है उसका कोई फायदा नहीं है। वह जब तक जमीन पर नहीं उतरती तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। उसे जमीन पर उतारने के लिए कौन से कार्यकर्ताओं की जरूरत है कौन से विधान सभाओं के सदस्यों की जरूरत है कौन से राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों की जरूरत है? पर हमने एक परम्परा सी बना ली है एक दूसरे पर दोषारोपण करने की।

अभी जिस तरह से बच्चों की बिक्री के बारे में बता रहे थे मैं इसी अखबार में पढ़ रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिनाई किया है कि ऐसी घटना नहीं घटी है। अभी मैं पीछे चुनाव लड़ने के लिए बिहार गया था और मैंने उस वक्त पढ़ा कि पश्चिमी चम्पारन में वहां दो जून की रोटी की जुगाड़ में बिहार के किसी ट्राईब्ल ने अपनी बच्ची बेच दी। तो मैं भी वह मसला यहां पर उठाऊं? उससे कोई अन्त होने वाला नहीं है। यह हमारे समाज में हमारे चेहरे पर काले धब्बे हैं। उन धब्बों को धोने की जरूरत है। पर हम यह सोचते रहें कि वहां लालू प्रसाद का राज है इसलिए मैं उठाता रहूं और वहां समीर रंजन का राज है इसलिए यह उठाती रहें तो यह नहीं चलेगा। इससे कोई सौल्यूशन नहीं निकलने वाला। इसका सौल्यूशन निकालने के लिए हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा कि राज्य में जो अन्न जाता है वह स्मगल हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है और सरकारी पदाधिकारी कोई कार्रवाई करते किसी स्मगलर को पकड़ते तो वहां किसी राजनीतिक दल को उसका संरक्षण देने के लिए बंद की कॉल नहीं देनी चाहिए? पर ऐसा होता आया है कि बंद की काल देते रहे हैं। बंगाली और आदिवासियों के बीच में क्यों फर्क डाला जाता है। तो यह किसने नारा लगाया था—अमरा-बंगाली का? अमरा-बंगाली पार्टी को जन्म देने वाली कौन सी पार्टी है मैं जानना चाहता हूं? बताए कोई सदस्य छाती पर हाथ रखकर कि किस पौलिटिकल पार्टी ने त्रिपुरा में अमरा-बंगाली को जन्म दिया था और किस पार्टी ने त्रिपुरा में त्रिपुरा के नौजवानों के हाथों में अस्त्र-शस्त्र पकड़ाये हैं? वह कौन सी पार्टी है? आज वह आदिवासी के नाम पर फिर से राज्य सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। आज वह बंगालियों के दिमाग में अमरा-बंगाली का नारा उठाकर आदिवासी और बंगाली के बीच में भेद करना चाहते हैं। वह कौन सी पार्टी है? ... (व्यवधान)

मैं तो अच्छी तरह पहचानता हूं आपको। क्योंकि मेरा जन्म तो मार्क्सवादी इलाके में हुआ है। तो इसलिए उत्तेजित करने की कोशिश न करें। झूठे आरोप न लगायें क्योंकि सब को पता है कि किसकी गिरेबान में क्या है।

तो ऐसी बात है कि आज यह जो संकल्प रखा है इस संकल्प का तरीका यह नहीं होना चाहिए कि हम किसी पौलिटिकल पार्टी में भेद करें। वहां डैथ हुई है आन्त्रशोध के कारण गैस्ट्रो एंट्राइटिस के कारण वहां डैथ हुई है कालाजार के कारण वहां डैथ हुई है हैजे के कारण। परन्तु ऐसे कालाजार की डैथ हमारे बिहार में भी होती है उड़ीसा में भी होती है पश्चिमी बंगाल में भी होती है नौर्थ बंगाल में भी होती है। पर आप खुद ही बतायें महोदया

कि सदन इस चीज पर कैसे विचार करे कि आन्त्रशोध की बीमारी का इलाज आज तक भारत में कोई नहीं कर सका। और उसका बड़ा ही लिमिटेड इलाज है। कालाजार का इलाज अभी तक नहीं हो रहा है और अगर हो रहा है और जिन डाक्टर्स को इलाज का पता है तो दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं और यदि दवाईयां उपलब्ध हैं तो उसकी कीमत इतनी है कि उस पर ब्लैकमार्केटिंग हो रही है व दवाईयों की शौर्ट सप्लाई है। मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा को इन दवाईयों की सप्लाई दी जाए वहां सप्लाई बढ़ाई जाए और सदन को बताने की कृपा करें कि वहां कितनी पौपुलेशन है और किस हिसाब से वहां राशन बांटा जाता है और राशन कार्ड कितने हैं यह सदन को बताया जाये? पर-केपिटा डिस्ट्रिब्यूशन वहां कितना है और दूसरे राज्यों को कितना है यह भी बताएं क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां पर-केपिटा डिस्ट्रिब्यूशन ज्यादा है जो कि स्मगल होकर बंगलादेश चला जाता है। आप महोदया त्रिपुरा चले जाइए पता लगेगा कि वहां बार्डर पर बंगाली लोग हिल्सा मछली बड़े शौक से खाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि बंगला देश में प्याज की कमी हो जाती है तो एक किलो प्याज की बनिस्बत दो किलो हिल्सा मछली मिल जाती है या एक किलो नमक के बदले दो किलो हिल्सा मछली मिलती है और बंगाली लोग बड़े शौक से खाते हैं। हमारे इलाके से उस चीज की सप्लाई बंगला देश को जाती है ट्रक लोडर्स जाते हैं और हमारे यहां इन चीजों में कमी आ जाती है। उसका कहीं न कहीं रविलीशन होता है और उस रिविलीशन को अगर बढ़ा चढ़ाकर अखबारों में लिखा जाए और वह खबरें सदन में आएं और चर्चा का विषय बनें तो मैं समझता हूं कि यह अफसोस की बात है। मुझे अफसोस है कि हम ऐसे पक्षों को लेकर लड़ पड़ते हैं। गरीबी है देश में, यह वास्तविकता है और यह वैसा ही सत्य है जैसा कि पूरब से सूरज निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है।

उस गरीबी को खत्म करने के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जब तक हम रूरल पुअर की देहात के इलाकों के गरीबों को परचेजिंग पावर नहीं बढ़ाते तब तक यह समाप्त नहीं होगी। जब तक हम उन हाथों को रोजगार नहीं देते तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी और उसकी शुरुआत हमारी सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री ने नयी इकनोमिक पालिसी और नयी इंडस्ट्रियल पालिसी से की है। किस तरह से ज्यादा से ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में क्रिएट किया जाए और रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज लगें और लोगों को नौकरियां मिलें और उसके साथ-साथ जो डेवलपमेंट पालिसी आई है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की उसमें जो 1711 ब्लाक रखे गए हैं उसमें काफी ब्लाक त्रिपुरा के लिए रखे गए हैं। मंत्री महोदय से मैं गुजारिश करूंगा कि वह बताए कि कितने ब्लाक रखे हैं और कौन से एरिया में रखे हैं। मुझे जहां तक जानकारी है ड्राऊट प्रोन एरिया, फ्लड प्रोन एरिया और ट्राइबल एरिया रखे गए हैं। उसमें त्रिपुरा भी आता है। बल्कि त्रिपुरा तो वैसे ही स्पेशल कैटेगरी में आता है। यहां पर और कोई गुंजाइश नहीं है कि और कुछ किया जाए क्योंकि जब तक आप लीकेज बंद नहीं करेंगे जब तक आप स्मगलिंग आफ फूडग्रेन्स टु बंगला देश बंद नहीं करेंगे तब तक आप जितना अनाज डालते जाएंगे वह निकलता जाएगा। उसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

महोदया, अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गरीबी तो युग-युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है। बेकारी तो युग-युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है। उसको समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को कोशिश करनी चाहिए और अलग-अलग होकर नहीं बल्कि इकट्ठा होकर कोशिश करनी चाहिए और उसको समाप्त करना चाहिए क्योंकि यह गरीबी ही सबसे बड़ा रोग है। इससे सारे रोग और महारोग पैदा होते हैं। इन रोगों को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब जनों

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया]

को मिलकर इसे रोकना चाहिए। गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी दूर हो गई तो बेकारी दूर होगी। बेकारी दूर होगी तो महामारी दूर होगी। इन सब चीजों का सहज उपाय यह है कि हम सबको मिलकर एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात नहीं करनी चाहिए, राजनीति से प्रेरित होकर एक-दूसरे की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, भावुकता का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए और अगर कोई गरीब मर गया है तो उसकी लाश से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना नहीं चाहिए।

श्री **संघ प्रिय गौतम**: आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से मैं श्रीमती सरला माहेश्वरी जी के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा लेकिन कुछ ऐसे तथ्य श्री अहलूवालिया साहब ने उठाए हैं, मैं उनसे भी सहमत हूं कि यहां पर हर मसले को राजनीतिक दृष्टि से पेश किया जाता है। अपवादस्वरूप मेरी पार्टी ने कभी किसी मसले को राजनीतिक दृष्टि से पेश किया होगा लेकिन मेरी पार्टी को छोड़कर आम तौर से यहां पर सभी राजनीतिक दलों के लोग यथार्थ से नहीं, राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा प्रेरित होकर मसलों को प्रस्तुत करते हैं। यदि यह बात सही है कि युग-युगांतर से गरीबी चली आ रही है तो इस देश में बड़े लंबे समय से हिंदुओं का राज रहा, मुसलमानों का राज रहा, ईसाइयों का राज रहा, सिक्खों का राज रहा लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं सब की बात कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि यह सब के ऊपर लागू होती है। जितनी भी चीजें हैं, देश की जमीन है, धरती है, कल-कारखाने हैं, लाइसेंस हैं, परमिट हैं, ऐजेंसियां हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, फ्लैट हैं, प्लाट हैं, शासन-प्रशासन शिक्षा-दीक्षा इन सब से महरूम रहे ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और आज भी सारे देश में जुल्म, अत्याचार के शिकार हैं तो ये, गरीबी के शिकार हैं तो ये, भुखमरी के शिकार हैं तो ये और जब कभी भी इनका मसला आता है तो हम वास्तविक बात से दूर हटकर सरकारों की बर्खास्तगी की मांग करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी के दिल में जरा सा भी रहम इन वर्गों के लोगों के लिए है तो साढ़े 22 प्रतिशत आबादी, सरकारी आंकड़े हैं, 1991 की जनगणना के आधार पर 25 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की है तो पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी धनराशि इनके लिए अंकित की जाती है? क्या कभी इन जातियों के विकास के लिए, इनके कल्याण के लिए आबादी में इनकी जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आवंटित की गई? कभी नहीं की गई? किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई। जब नहीं की गई तो इनका आर्थिक विकास कैसे हो सकता है? इनकी गरीबी कैसे दूर हो सकती है? इनकी भूखमरी का समाधान कैसे हो सकता है? क्या कभी जो योजनाएं इनके लिए बनाई वह कार्यान्वित की गई? मैं फिर मूल विषय पर आऊंगा, मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका में इसलिए जाना चाह रहा हूं कि जो योजनाएं इन लोगों के लिए बनाई गई वह कभी कार्यान्वित नहीं की गई। अहलूवालिया जी की बात से मैं सहमत हूं लेकिन मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक संसाधन उनके पास थे, त्रिपुरा में कांग्रेस की सरकार रही है, दूसरी भी सरकारें रही हैं, लेकिन उनके साधन उनसे छीन लिए गए। यह सही है कि भुखमरी साम्यवादी सरकार में कम थी और कांग्रेस सरकार में ज्यादा बढ़ी है परन्तु यह भी सही है कि वह आदिवासी क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है जिनको हम बिगाड़ते हैं। इनफिल्ट्रेशन जो हुआ है बंगला देश से वह कांग्रेस की शह पर हुआ, वोट की राजनीति के लिए हुआ। चकमा भी आए बंगला देश से लेकिन वह आए नहीं थे, वह भगाए गए थे, वह निकाले गए थे, उनको मजबूर किया गया था। जब उनकी वापसी की बात कही गई तो उनका कोई इंतजाम किया नहीं गया बंगला देश में वह वापस लिए नहीं गए। बंगलादेश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठे, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे जो लोग यहां

पर धर्म के नाम पर बड़े-बड़े लांछन लगाते हैं, बंगला देश से जो बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए उसमें एक विशेष वर्ग के लोगों की संख्या अधिक हैं। कांग्रेस के लोगों ने केवल वोट की राजनीति के लिए उन लोगों को नागरिकता प्रदान की। आज उनकी संख्या इतनी बड़ी हो गई है। यह भी सही है कि जितनी तस्करी बंगला देश से हो रही हैं, जितनी अशान्ति आज त्रिपुरा में है, उसका सबसे बड़ा कारण इन लोगों की घुसपैठ है जिसमें ज्यादा एक विशेष धर्म से संबंधित है। हमारे साम्यवादी भाई भी कभी उस सत्य को प्रकाशित करने में हिचकिचाते हैं।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि क्या वे योजनाएं कार्यान्वित हुई जो इन जातियों के लिए बनीं? जितने इनके प्राकृतिक साधन थे, इन वनवासियों के जो जंगलों के बीच में जो जमीन खाली पड़ी हुई थी जिसे हम परती जमीन कहते हैं, उसको जोतकर वह खेती करते थे। जंगलों की लकड़ी और फल-फूल बेचकर जंगलों के पत्ते बेचकर वह गुजर बसर करते थे। कांग्रेस राज में सारे देश में सारे जंगलों के जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे ये आदिवासियों से छीन लिए गए और आज वे जमीन के मालिक नहीं है। टेनेंसी ऐक्ट में भी यह कहा गया है कि एक निश्चित अवधि से किसी जमीन पर जो काबिज है वह उसका मालिक हो जाएगा। लेकिन सदियों से जंगलों की जमीन पर काबिज रहते हुए भी ये आदिवासी जमीन के मालिक नहीं हो सके। उनको प्रोप्राइटरी राइट्स किसी सरकार ने नहीं दिए चाहे वह मध्य प्रदेश में हों, चाहे महाराष्ट्र में हों, चाहे त्रिपुरा में हों। उनको प्रापर्टी राइट नहीं मिला, जमीनें छीन ली गई, फल लकड़ी, फूल-पत्ती, फल चुनने के अधिकार छीनकर ठेकेदारों को दे दिये गये। उनकी सम्पत्ति को छीन लिया गया। उनकी बहू-बेटियों के साथ ये ठेकेदार अनैतिक कार्य करने लगे। बाजार में लेजाकर उनको बेचने लगे। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? यहां तो कांग्रेस के लोग और त्रिपुरा में कम्युनिस्ट लोग, ये दोनों जिम्मेदार है। ये इनके घड़ियाली आंसू हैं। कभी आवाज उठाई कि इनके संसाधन वापस होने चाहिए? कभी आवाज उठाई कि पंचवर्षीय योजना में उनकी जनसंख्या के आधार पर धनराशि आबंटित होनी चाहिए? मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप घड़ियाली आंसू मत बहाइये। ये सारे आंकड़े बताते हैं त्रिपुरा की स्थिति को। यह स्थिति क्यों बनी? यह स्थिति इसलिए बनी कि जो रूरल एम्प्लायमेंट डवलपमेंट स्कीम थी उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। जितने लोगों को एम्पलायमेंट मिलना चाहिए वह नहीं मिला। सन् 1989-90 के लिए 60 करोड़ रुपये आबंटित किये गये लेकिन प्रदेश सरकार ने केवल 18 करोड़ रुपये रिलीज किये। सन् 1990-91 के लिए 55 करोड़ आबंटित किये लेकिन कुल 7 करोड़ रुपये रिलीज किये। इस तरह से जो ग्रामीण विकास की योजनाएं थी जो रोजगार संबंधी थीं वह पूरी नहीं हो पाई। दूसरे प्रकृति के प्रकोप से फसल मारी गई। तीसरे पानी नहीं मिला। एक तरफ पैदावार नहीं हुई और दूसरी तरफ पैसा नहीं मिला। इससे विकास का काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ आबादी का भार बराबर बढ़ता चला गया तो फिर यह गरीबी और भुखमरी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा। किसी ने भी इस पर सोचा? घुसपैठ को रोका जाना चाहिए। आज जो त्रिपुरा की स्थिति है वह सारे देश की स्थिति भी है। महोदया, मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं बड़े दुख के साथ जो सारे देश से संबंधित है। यह देश आर्थिक दृष्टि से बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। आबादी बढ़ती जा रही है, चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ अनाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, अश्लील साहित्य का प्रकाशन बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, उग्रवाद बढ़ रहा है, देश के अंदर व्यक्तिगत धन संचय करने

[श्री संघ प्रिय गौतम]

की प्रवृत्ति बढ़ रही है, फिजूलखर्ची की प्रवृत्ति बढ़ रही है । हमारी आर्थिक योजनाएं ठीक ढग से काम नहीं कर रही हैं। हमारी नई आर्थिक नीति व नई उद्योग नीति ऐसी बनी है कि आज पिछड़े क्षेत्रों में कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं है । अगर कोई उद्योग लगायेगा तो ऐसी चीज बनायेगा जो घरेलू उद्योगों में बनती है । घरेलू उद्योगों की चीज अगर बड़ा उद्योग बनायेगा, मंझला उद्योग बनायेगा तो घरेलू कामकाज सारा समाप्त हो जायेगा । जैसे चौबे जी गये छबे जी होने मगर दूबे जी रह गये । ये गरीब लोग जिन को आप बढ़ाना चाहते हैं काम के अभाव में, कुटीर उद्योगों के अभाव में, एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री के अभाव में ये और ज्यादा गरीब हो जायेंगे, बेरोजगार हो जायेंगे । दूसरी तरफ आज जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं बैंकिग प्रणाली को उनके हक में देकर गरीबों को जो पैसा मिलता था वह बन्द हो जायेगा । नौकरी मिलती वह बन्द हो जायेगी। नये एवेन्यू नौकरी के नहीं रहेंगे । इससे बेरोजगारी इस मुल्क में बढ़ेगी । यह है आपकी थोथी और धोखाधड़ी वाली उद्योग नीति, अर्थ नीति। इसमें अमीर और अमीर होगा, गरीब और ज्यादा गरीब होगा । क्योंकि इस देश का आदमी पाखंडी है राजनीतिक लोग यह जानते हैं । पाखंड के चक्कर में इन गरीबों को उलझा दो तो यह अपनी भुखमरी की बात को भूल जायेगा । सारा समय इस सदन का आप मंदिर और मस्जिद के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं।.. (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मंदिर का झगड़ा.. (**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम : आप सदन का सारा समय इसमें बर्बाद करते हैं जिससे गरीबों का कोई मतलब नहीं ।... (**व्यवधान**) इस मंदिर मस्जिद के मामले में कोई झगड़ा नहीं हुआ और न कोई आदमी मरा, लेकिन भूख से अनेकों लोग मारे गये । आज स्थिति यह है कि पेट न तो साम्यवादियों का थमता है और न ही जनता दल के लोगों के पेट का पानी थमता है और न कांग्रेसियों का थमता है । जब मंदिर मस्जिद की बात करते हैं मगर हमारे पेट का पानी तो थमा हुआ है। जो समस्या बहुत सालों से अदालत ने हल नहीं की, राजनीतिज्ञों ने तय नहीं की, उसको हमने हल करने का प्रयास किया है ।

We have got the political will to solve the problem.

हमारी इच्छा शक्ति है । आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं । आपको आदिवासियों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कोई चिन्ता नहीं है। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में अनेकों कांड हुये । गुजरात के अन्दर लोग मारे गये किसी ने आवाज नहीं उठाई। आंध्र प्रदेश के अन्दर लोग मारे गये, इनके पास इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। सरकार भंग करने की बात हम नहीं करते हैं । लोग मारे जाते हैं। इसका क्या उपाय है ।

Let the actual tiller of the soil be the owner of the soil.

मैं यह कहना चाहता हूं कि जमीन जोतने वाले की होनी चाहिये और फैक्टरी में काम करने वाले फैक्ट्री का मालिक होना चाहिये । देश में सच्ची-नागरिकता की सबसे बड़ी परख यह है कि जो देश की सेवा करता है, देश का निर्माण करता है, वह सबसे बड़ा देश भक्त है । जो देश से द्रोह नहीं करता, तस्करी नहीं करता, वह सबसे बड़ा देश भक्त है । इस दृष्टि से देखा जाय तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग सबसे बड़े देश भक्त हैं। वे देश का निर्माण करते हैं, देश की सेवा करते हैं । आज तक उन्होंने खालिस्तान की मांग नहीं की, पाकिस्तान की मांग नहीं की, बोडो लैंड की मांग नहीं की, गोरखा

लैंड की मांग नहीं की, दलितस्तान की मांग नहीं की और न ही तमिल लैंड की मांग की है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग भारत भूमि को अपनी भूमि मानते हैं। वे रोटी की मांग करते हैं, कपड़े की मांग करते हैं, मकान की मांग करते हैं, दवा की मांग करते हैं, शिक्षा की मांग करते हैं, सुरक्षा और न्याय की मांग करते हैं और अपनी इज्जत की सुरक्षा की मांग करते हैं। इसलिये मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन लोगों की तरफ ध्यान दीजिये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि त्रिपुरा में जो पैसा, जो धनराशि आवंटित की गई थी, ग्रामीण विकास के लिये जो पैसा रखा गया था उसको रिलीज किया जाय। वहां जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम बनाये गये थे वे इंपलीमेंट नहीं हुये हैं। वहां पर प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसल नहीं हुई। लोगों को पानी नहीं मिला जिससे बीमारियां फैली। बीमारी के कारण लोग भूखमरी में शामिल हो गये। त्रिपुरा के अन्दर आबादी बढ़ गई। वहां पर घुसपैठिये आ गये। वहां पर तस्करों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि बराय मेहरबानी करके श्रीमती सरला माहेश्वरी ने जो मांग की है कि वहां कोई अस्थायी व्यवस्था की जाय और खाने-पीने की चीजें लोगों को दुगुने और तीगुने रूप में सप्लाई की जायें। आज वहां पर स्थिति यह है कि लोग अपने राशन कार्ड बेच रहे हैं। चार रूपये के लिये अपनी चार साल की बच्ची का पेट भरने के लिये एक महिला ने 130 रु० में एक साहूकार को अपना राशन कार्ड बेच दिया। साहूकार लोग इन राशन कार्डों से राशन लेकर ब्लैक में बेचते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन राशन कार्डों को वापस कराया जाय और साहूकारों को गिरफ्तार किया जाय। इन पर रोक लगायी जाय और राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है तो केन्द्र सरकार, क्योंकि यह आदिवासी, वनवासी क्षेत्र है, इसलिये केन्द्र सरकार पैसा रिलीज करे जो वहां के विकास कार्यों पर लगाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती सरला माहेश्वरी जी धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी हरी सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आदरणीया सरला माहेश्वरी जी के संकल्प पर सदन में विचार हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। उन्होंने मुल्क में जो गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी फैली है, उस ओर अपने संकल्प द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। यह संकल्प किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं बल्कि इन्होंने अपने संकल्प को बहुत ही सीमित रखकर त्रिपुरा में भूखमरी की वजह से जो मृत्यु हुई है, उस तक उन्होंने इसको सीमित रखा है। प्रश्न यह उठता है कि विशेष तौर से त्रिपुरा में ही क्या ये मौतें हुई? अपने भाषणों में दूसरे साथियों ने भी कहा कि कांग्रेस की हुकूमत द्वारा योजनायें लागू न करने की वजह से, शासन में कमियों की वजह से ये मौतें हुई हैं। लेकिन मैंने जो अखबारों में पढ़ा उनमें साफ तौर से यह कहा गया और मुख्य मंत्री ने भी कहा कि आंत्रशोथ से, हैजे से तथा पेट की दूसरी बीमारियों से जो पानी पीने से होती हैं, उनकी वजह से ये मौतें हुई। अन्न के न मिलने की वजह से, भूखमरी से ये डेथ नहीं हुई। यह सब अखबारों को पढ़ने से मिलता है। महोदया, आप जानती हैं कि हमारे जो समाचार-पत्र हैं, उनकी सूचनायें पूर्ण होती हैं लेकिन अगर हम ऐसा मानकर भी न चलें तो हमारी सेंटर की टीम वहां गयी थी। जब यह बात आयी कि यहां पर भुखमरी बढ़ रही है तो हमारी केन्द्र सरकार की तरफ से एक टीम वहां गयी, यह देखने के लिये वहां पर क्या अन्न की कमी है, वहां पर अन्न की सप्लाई है या नहीं है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अन्न की सप्लाई को दस हजार से बढ़ाकर पन्द्रह हजार टन कर दिया गया है। साथ ही इस दौरान जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गयी, वह पांच करोड़ रुपये की एकदम इस सिचुएशन को मीट आउट करने के लिये खासतौर से केन्द्र सरकार की ओर से

[चौधरी हरि सिंह]

दी गयी । जैसा कि कहा गया कि केन्द्र सरकार ने कोई सहायता नहीं दी और इसको हल्के फुल्के ढंग से लिया ऐसी बात नहीं है । जो प्राबलम वहां पर है, यह जो समस्या वहां पर है, आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि त्रिपुरा की आबादी 75 हजार के करीब है लेकिन वहां पर सवा लाख राशन कार्ड इश्यू किये गये हैं । इन राशन कार्डों से राइस, चावल आदि लेकर यह सब बंगला देश को भेज दिया जाता है । आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि बंगला देश को जो चीजें स्मगल होकर जाती हैं उनसे 5 करोड़ रुपया मंथली त्रिपुरा में आता है, यह भी अखबारों में छपा है । खाने-पीने की चीजें, नमक, माचिस, मिट्टी का तेल और जो कपड़ा हैं ये सारी चीजें वहां से बंगला देश जाती हैं और विशेषतौर से चावल वहां जाता है, यह अखबारों में छपा है । मैंने पढ़ा है कि वहां से चावलों के ट्रक भर भर कर बंगला देश जाते हैं । समस्या यह नहीं है कि केन्द्र सरकार ने उनको राशन नहीं दिया, या उनके पास राशन नहीं पहुंच सका . . (व्यवधान) . .

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आदरणीय सदस्य-गण आपस में बातचीत न करें और करें तो उसका वैल्यूम बहुत नीचा रखें ।

चौधरी हरि सिंह : वहां पर जो फूड सप्लाई है वहां कुछ ऐसे तत्व पैदा हो गये हैं जो स्मगलिंग पर जिंदा रहते हैं । इसके कारण वहां के जो भोले भाले लोग हैं उनको जो कुछ मिलना चाहिये वह उनको नहीं मिल पाता । जब बीमारी का दौर वहां पर चला तो हमारी केन्द्र सरकार ने केन्द्र से एक मेडिकल टीम वहां भेजी और वहां पर तीन करोड़ रुपये की दवाइयां भेजी । बेबी फूड से लेकर पुरुषों के लिये विटामिन-सी और विटामिन-बी कम्पलेक्स जो आदमियों को ताकत और एनर्जी देता है वहां पर करोड़ों रुपये की पहुंचायी गयीं । जो लोग कहते हैं कि उस स्टेट को आइसोलेट किया जा रहा है, वहां केन्द्र सरकार द्वारा तवज्जह नहीं दी जा रही है, यह बेबुनियाद बात है, इसका कोई आधार नहीं है । केन्द्र सरकार ने ऐसी सिचुएशन में जो पासिबल स्टेप, कदम हो सकते थे, फाइनेंशियली लिये और वहां पर फूड सप्लाई, मेडिसंस, डाक्टर्स नर्सेज इन सब का प्रबंध त्रिपुरा के लिये युद्ध स्तर पर किया । आप कहते हैं कि वहां पर क्योंकि कांग्रेस का शासन है इसलिये त्रिपुरा में भुखमरी और डैथ हो रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि आपके उड़ीसा में किस का शासन है ? आपके मध्य प्रदेश में अभी भी लोग भूख से मर रहे हैं । हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहां से होकर आये हैं हमारे मिश्रा जी बैठे हैं । इनके जिले में मरे हैं, मध्य प्रदेश में लोग मरे हैं । यह कहना कि शासन वाले मार रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है । (व्यवधान) स्टारवेशन डेथ नहीं हुई । यह जो इस तरह का आरोप लगाया जाता है इसकी बुनियाद में किसी पार्टी के शासन को बदनाम करने की नीयत होती है । मूल कारण इसका यह है कि हमारी छोटी छोटी स्टेटें हैं । मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि छोटी छोटी स्टेट, लोग यह जरूर कहते हैं कि हरियाणा स्टेट बड़ी एफिसियेंट है क्योंकि वह छोटी है । लेकिन यह स्टेट जो एकानामिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हो गयी है इसकी वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है । दिल्ली यहां से करीब है और हर आदमी दौड़ता है और चाहता है कि मेरी इंडस्ट्री हरियाणा में लगे ताकि दिल्ली हमारे पास हो । इसलिये हरियाणा की एकानामी सुधरी है और सुधरेगी । लेकिन जो दूर दूर के हमारे राज्य हैं ये एकानामिक तौर पर खुशहाल इसलिये नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन होगा दूर होने के कारण उसकी लागत ज्यादा होगी और किराया बढ़ जाने से उसकी खपत की पूर्ति नहीं हो सकती । वहां पर तो छोटी चीजें जैसे लकड़ी का काम है, जो वनों में पैदा होने वाली चीजें हैं उन सब से लोकल एकानामी जरेनेट की जा सकती

है । लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि जितनी भी ऐसीहस्टेट्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो इनमें कुछ ऐसे तत्व पैदा हो गये हैं जो आतंकवादी हैं । हर एक जगह नौजवान हाथों में गन, राइफल, रिवाल्वर और ए-के47 लेकर चलते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन बन्द चलता रहता है । न कालेज खुले रहते हैं और न बाजार खुले रहते हैं । यह जो वातावरण इन राज्यों में पैदा हो गया है इस वातावरण के चलते ये स्टेटस प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती हैं और आर्थिक तौर पर उन्नति नहीं कर सकती हैं । किस तरह से उत्पादन हो, कैसे अन्न पैदा हो, सेल्फ सफिसियेंट स्टेट को बनाने के लिये, वहां की पापुलेशन को ऊपर उठाने के लिये जो काम है वह हो नहीं पाते हैं । वहां पर सरकारी कर्मचारी रहना नहीं चाहते । अगर किसी कर्मचारी का दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया जाय तो वह सौ कोशिश करेगा कि यह ट्रांसफर कैंसिल हो जाय । अगर वहां पर इस तरह का वातावरण बना हुआ है तो वहां पर आर्थिक तौर पर किस तरह से खुशहाली आ सकती है, आर्थिक तौर पर स्टेट किस तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है ? वहां पर चावल की पैदावार बढ़ाना, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना कैसे संभव हो सकता है ? इसलिये इस वातावरण को न पैदा होने देने के लिये वहां की जो पापुलेशन है, वहां की जो आबादी है उसके मन में यह धारणा आनी चाहिये कि यह जो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ाना चाहिये । हमारी सरकार ने, मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है उसका विशेषतौर से इस बात की ओर ध्यान रहा है कि जो आदिवासी एरियाज हैं, जहां पर 25-30 परसेंट आबादी ट्राइबल्स की है, वहां की विशेष तरक्की के लिये अनेक योजनायें बनाई हैं, रोजगार की हैं, उनके बैंक लोन, उद्योग धंधे, स्कूल और कालेज के बारे में, हर तरीके से जो डेवलपमेंटर, विकास की योजनायें हैं, इस सरकार ने उनकी तरफ तवज्जह दी है । असम के बारे में मिसाल देकर कहना चाहता हूं । असम में चाय का प्रोडक्शन होता है वह सारे हिन्दुस्तान के प्रोडक्शन का 60 प्रतिशत है । लेकिन वहां भी हालात खराब होते जा रहे हैं । वहां चाय का लेबरर, चाय पैदा करने में जो कम्पनी की मदद करता है वह और अन्य अधिकारी वहां जाने से कतराते लगे हैं । वह वहां जाने में घबराते हैं । नतीजा यह होगा कि आने वाले सालों में चाय का प्रोडक्शन भी गिर जायेगा । इसमें जो एकानामिक कंडीशन है, जो आर्थिक अवस्था है वह दुर्गति की व्यवस्था तक पहुंच जायेगी । तो समस्या इस बात की है कि जो इन स्टेटों में इस तरह का वातावरण पैदा हो गया है इसको रोकना बहुत जरूरी है । तीसरा यह है कि त्रिपुरा में बहुत से जाली राशन कार्ड चल रहे हैं इसकी जांच कराई जानी चाहिये और जाली राशन कार्डों को खत्म करना चाहिये जिससे सब को राशन मिल सके । यह व्यवस्था होना बहुत जरूरी है । इसलिये मैं सरकार से यह कहूंगा कि विशेष दस्तों से जांच करवा कर इसको ठीक करना चाहिये । हमारी सीमाओं पर चावल, अनाज और चीनी आदि की स्मगलिंग हो जाती है । इसको रोकने के लिये हमारी सीमाओं पर बहुत चुस्त, माकूल और सख्त प्रबंध होना चाहिये कि खाने पीने की चीजें बाहर नहीं जा सकें तभी इस अवस्था को सुधारा जा सकता है । गरीबी, बेरोजगारी की समस्या सारे देश के अंदर है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार हो या जो भी सरकार हो सब के सामने समस्यायें बनी रहेंगी, खड़ी रहेंगी । भारत सरकार तो गरीबी को दूर करने के लिये प्रयत्नशील है । 1947 के पहले भी हमारे देश में गरीबी थी : मेरे से पूर्व वक्ता मुंशी प्रेम चन्द की बात कह रहे थे । मुंशी प्रेम चन्द ने अपनी रचनाओं में छोटे पनवाड़ी से लेकर चित्रण किया है । वाकई में मुंशी प्रेम चन्द का होरी और कहां हमारे देश का किसान है । आज उसके जीवन में परिवर्तन आया है । लेकिन मैं यह कह रहा था जहां मुंशी प्रेम चन्द ने गरीबी का चित्रण किया है वहां अच्छी आर्थिक अवस्था का भी चित्रण अपनी कलम के

[चौधरी हरि सिंह]

जरिये किया है । इससे कांग्रेस आंदोलन को बड़ी दिशा दी है। कुछ पुस्तकें ऐसी रहीं हैं, हमारे सरदार साहब ने जिनका जिक्र किया और श्रीमती सुरला माहेश्वरी जी ने भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । जो व्यापारी वर्ग है वह चीजों के भावों में उतार-चढ़ाव के कारण गरीब लोगों का शोषण करता है। जो ट्रेडर्ज हैं वह मुनाफाखोरी करते हैं। छोटी स्टेटस में तो यह मोनार्क होते हैं । ट्रेडर सारी इकोनोमी को कंट्रोल करते हैं, सारी इकोनोमी उनके हाथ में खेलती है । शासक भी कुछ नहीं कर पाते हैं । अफसर कुछ नहीं कर पाते हैं । राजनेता कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे शासत तंत्र का ट्रेडर्ज नाजायज शोषण करते हैं और मुनाफा कमाते हैं और चीजों को कार्नर कर लेते हैं। आज यदि रेल पटरी से उतर गई तो दो चार रोज समान नहीं आयेगा। ट्रेडर सारी कमोडीटीज को कानर कर देते हैं, छिपा लेते हैं, गायब कर देते हैं। इससे भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है । त्रिपुरा में अनाज न पहुंचने की समस्या नहीं है, असली समस्या यह है कि इसका सुचारू रूप से इंतजाम होना चाहिये । जहां से हमारी सीमाओं से स्मगलिंग होती है, उसको रोकना चाहिये। भारत सरकार तो गरीबी को खत्म करने के लिये जुटी हुई है। सारी योजनायें और स्कीमें हैं और लोन की भी सुविधायें हैं । यह इतना बड़ा भारी काम है। इसमें हमारे विरोधी दलों के नेताओं की भी राय रहती है। एक्सपर्ट लोगों की राय भी रहती है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा योजना बनाकर पुलिंदा बना कर चिट्ठा दे दिया और फरमान मिल गया । ऐसा नहीं होता है। इस पर बड़ा डिसक्शन होता है। कौन नहीं चाहता कि गरीबी खत्म हो, कौन नहीं चाहता कि देहात में पीने का पानी न मिले, कौन नहीं चाहता कि सारे देश के अन्दर स्कूल-कालेज और डिसपेंसरीज न खुलें, कौन नहीं चाहता कि सभी लोगों को रहने के लिये मकान उपलब्ध न हो और खुले आसमान के नीचे लोगों को न सोना पड़े ? मकान देने की सरकार की योजना है । सारी योजनायें हैं लेकिन यह सब कोई जादू का डंडा घुमाने से नहीं हो सकता । मैं तो यह कहता हूं कि कांग्रेस की यह इसी खुबी रही है कि उसने देश को आर्थिक रूप से अपने पांव पर बड़ा किया है। इकोनोमिक जेनरेशन किया है। आज आप पड़ोसी देश पाकिस्तान की अंदरूनी आर्थिक हालात देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वहां इकोनोमिक जेनरेशन नहीं है। बाहर से मिडल ईस्ट से नौकरियों से रुपया आ रहा है । जिस दिन नौकरी मिलना बन्द हो गया उस दिन पाकिस्तान आर्थिक तौर पर धड़ाम से गिर जायगा । मुझे खुशी है कि भारत सरकार की सारी योजनायें और प्रयास है जिसके कारण हम अपने पांव पर खड़े हैं जबकि यूरोप में संकट है, रूस में भी आर्थिक संकट आ गया । वहां पर खाने पीने की चीजों का अकाल है । लेकिन हम अपने आत्म सम्मान के साथ जिंदा हैं। कांग्रेस सरकार गरीबी को खत्म करेगी, यह राष्ट्रव्यापी समस्या है, इसको हल करेगी। इन अल्फाज के साथ मैं समझता हूं कि जो डेथ्स हुई हैं यह भुखमरी की वजह से नहीं हुई हैं। धन्यवाद ।

4.00 P.M.

श्रीमती कमला सिंह (बिहार) : महोदया, मैं श्रीमती सरला माहेश्वरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करती हूं । बहिन सरला जी जब बोल रही थी त्रिपुरा के बारे में और त्रिपुरा के बारे में जब तथ्यों को रख रही थी, घटनाओं को उजागर कर रही थीं सदन के सामने तो उस समय बंकिम चन्द्र की "आनन्द मठ" जो भुखमरी की कहानी है वह मुझे याद आ रही थी। इसमें बंकिम चन्द्र ने वर्णन किया था कि भुखमरी के कारण किस तरह से मातायें अपनी संतानों को पकाकर परिजनों को दे रही थीं, किस तरह से मानव एक दूसरे मानव का मांस खा रहा था, किस तरह से परिजनों को भेजा गया था। यह कोई कहानी नहीं थी। यह सचमुच में उस समय 1872 के अविभाज्य बंगाल में, जो बंगाल, आसाम, उड़ीसा और बिहार को मिलाकर प्रांत था, उसमें अकाल पड़ा था । उस अकाल के बाद अंग्रेजों

ने क्या किया था। उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी। उस समय अंग्रेजों ने इस देश को तीन चीजें दी थीं। अकाल संहिता, फेमिन कोड जो आज भी हमारे देश में लागू है, कोई उसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं है, जस का तस वह फेमिन कोड आज भी लागू है, दूसरा, इस देश को दी थी पहली सिंचाई परियोजना। जो सोन परियोजना बनी थी वह उसी समय 1872 के साल में बनी थी और पटना शहर में एक अनाज का बहुत बड़ा गोला बना था जिसको आज भी लोग गोलघर कहते हैं।

महोदया, उसके बाद मुझे याद दूसरी कहानी 1967 की। इस देश के अनेक प्रांतों में उस समय संविद की सरकार थी। आपको याद होगा। हमारे बिहार प्रांत में थी — मैं बिहार से आती हूं — अकाल पड़ा हुआ था। अनेकों प्रांतों में भंयकर सुखाड़ था, लोग भूखे मरने की स्थिति में आ गये थे। उस समय संविद की सरकार ने जब केन्द्र की सरकार को कहा कि हमारे यहां अकाल है, लोक भुखमरी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और इसलिये राहत देनी चाहिये तो केन्द्रीय सरकार ने यह कहा कि कोई भुखमरी से मर नहीं सकता। हमारे देश में कोई भुखमरी से कानूनन मर नहीं सकता। सरकार या सरकारी अस्पताल का कोई डाक्टर यह सर्टिफिकेट नहीं देगा कि इस आदमी की मृत्यु स्टारवेशन डेथ है। यह कहेगा कि माल न्यूटीशन आंत्रशोध या अन्य बीमारी के कारण हुई है लेकिन स्टारवेशन डेथ कहना गैरकानूनी है। कानूनन इस देश में कोई भूख से नहीं मर सकता। तो उस समय भी यही हालत थी। नतीजा यह हुआ कि संविद सरकार ने फिर से कहा कि हमारे यहां लोग भूख से मर रहे हैं आप नहीं मानेंगी तो हमें बाध्य होकर फेमिन कोड लागू करना पड़ेगा। बिहार में फेमिन कोड लागू किया गया और लागू होने के बाद क्या होता है? जहां पर फेमिन कोड लागू होता है वहां सारा विकास का काम सब काम रोक कर अकाल से लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाता है। बिहार में यही किया गया था उस समय मुझे याद है। जो गरीब, है निर्धन हैं, पिछड़े हैं आदिवासी हैं। ऐसे लोगों को लाल कार्ड दिए गए थे अनेको विदेशी देशों को सहायता मिली थी। अनाज बांटा गया था। पीने के पानी को गांव गांव में पहुंचाया गया और मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि उस समय हमारी सरकार अगर नहीं बनी होती संविद की सरकार नहीं बनी होती तो लोगों को बचाया नही जा सकता था। किसी एक व्यक्ति को उसके बाद हमने मरने नहीं दिया।

महोदया इसी सदन में कोटैया जी ने एक मुद्दे को उठाया था पिछले सत्र में आंध्र प्रदेश में बुनकरों की भूखमरी के कारण मृत्यु। वे तो सी० पी० आई० "एम" के सदस्य नहीं थे वे तो जनता दल के नहीं थे बी० जे० पी० के नहीं थे वे शासक दल के थे और मैंने उनका इन्टरभ्यू भी कई जगह पढ़ा जो उन्होंने मैगजीन्स में दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार की नीति के कारण हजारों बुकर आज भुखमरी के कगार पर हैं और भूखे मर रहे हैं। भूख से मर चुके हैं लेकिन आन्ध्र प्रदेश की सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी और इस सदन में चर्चा के बाद भी सरकार ने कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया।

सरला जी ने अपनी व्यथा के कारण समाजिक प्रतिबद्धता के कारण जिस बात को इस सदन में के सामने उजागर किया है वह निश्चित रूप से चिंतनीय बात है। त्रिपुरा एक विशेष भौगोलिक स्थिति का प्रांत है त्रिपुरा जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा प्रांत एक बार्डर प्रांत है सीमावर्ती प्रांत है। त्रिपुरा से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो हमारी छल चातुरी उतने समझते नहीं हैं जिसके कारण वह शोषण के शिकार होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं।

[चौधरी हरि सिंह]

महोदया यह कोई साधारण बात नहीं है । जब कोई मां अपनी संतान को बेच दे, यह कोई साधारण बात नहीं है कि अपनी गोद के एक साल के बच्चे को उठा कर किसी को दे दे एक मुठ्ठी अनाज के लिए और यह घटनाएं वहां घट रहीं हैं और उसके बाद भी सदन में जो सरकारी पक्ष में बैठे हैं दो माननीय सदस्य वह इस तरह से बोल रहे ह जैसे कि यह केवल सत्ता के कारण, लालच के कारण यह बातें उठाई गई हैं । थोड़ा सा तो मानवता का बोध होना चाहिए हृदय में थोड़ी सी तो साधारण लोगों के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए थी; बाकी बात को जाने दीजिए ।

महोदया, भारतवर्ष एक वैल्फेयर स्टेट है और हमारे देश की यह प्रतिबद्धता है संविधान की प्रतिबद्धता है---

We are committed to greater good to greater number.

गांधी जी ने कहा था "अंतोदय"। वहां तक आप हम पहुंच नहीं पाये लेकिन उनके लिए हम प्रतिबद्ध हैं उनके लिए कुछ तो करें । कोई बात सामने आती है बिना टीका-टिप्पणी के उनके मुंह में अनाज का इंतजाम तो करें । यह तो सत्य है कि वहां खेती मारी गई है वहां फसल नहीं हुआ सूखा पड़ रहा है और लोग अपने संतान बेच रहे हैं और यह भी सत्य है कि कांग्रेसी हुकुमत में पिछले दो साल से सैंकड़ों अन्याय, अत्याचार की घटनाएं घटी है।

महोदया मेरे पास आंकड़े हैं । यह 1990 का है—एक दल वहां जांच करने के लिए गया था और उसने पाया कि 282 खून हुए थे आर्सन की घटनाएं 598 थीं

violet entrances into the house and attacks, 1324; kidnappings, 167; rapes, 31; dacoities, 166; attacks with sharp-cutting weapons, 618; hospitalised in these incidents, 3,078; post-mortem conducted on, 315; total number of cases registered in police station due to these actions, 24,438; total number of accused in these cases, 29,835.

महोदया मैं इस दस्तावेज में जो अन्य बातें हैं उनको उठाना नहीं चाहती। इतनी ही बातें काफी हैं कि वहां किस तरह की हुकूमत है कैसी हुकूमत वहां चल रही है इससे प्रमाणित हो जाता है।

महोदया लोग भुखे तो मर रहे हैं और कई लोगों ने कहा कि गरीबी के कारण—मूल बात है गरीबी इसे दूर करो बिलकुल सही बात है—मूल बात है गरीबी दूर करो।

महोदया, लोग भूखे तो मर रहे हैं और कई लोगों ने कहा कि गरीबी के कारण—मूल बात गलरीबी है गरीबी, इसे दूर करो बिलकुल सही बात —मूल बात है गरीबी दूर करो ।

मैं दो दिन पहले समाचार-पत्र में एक समीक्षा पढ रही थी । उसमें यह आया था कि पिछले एक वर्ष में भारतवर्ष में दो करोड लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए । हमारा शासन तंत्र आज की जो वर्तमान हुकूमत है, उसके कुशासन के कारण महंगाई इतनी बढ़ी है, उसके कारण एक करोड लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए आज के दिन में, तो आगे चल कर क्या होगा । कई लोगों ने कहा हमारी अर्थ नीति ही है, उसके कारण यह हो रहा है, मैं भी इसको मानती हूं कि हमारी वर्तमान सरकार की जो अर्थ नीति है, उसके कारण मैं भी इसको मानती हूं कि हमारी वर्तमान सरकार की जो अर्थ नीति है उसके कारण हमारा देश गरीब होता जाएगा। हमारा शोषण बढ़ेगा विदेशी तंत्रों का शोषण बढ़ेगा। यह बात सत्य है कि राजनीतिक दृष्टि से हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम गुलाम बन रहे हैं और बनते जायेंगे। उस गुलामी तंत्र में हमारे देश की जो शोषित पीड़ित जनता है उसके कल्याण के लिए कोई काम होने वाला नहीं है। मैं बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहती हूं कि हमारा दल, जनता दल ने सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम के तहत आदिवासी हरिजन गिरिजन और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं सामाजिक दृष्टि से शोषित लोग हैं इनके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करके नके विकास के लिए हमने कार्यक्रम

शुरू किया है जिसके कारण हमको सरकार भी छोड़ना पड़ा उससे हमें कोई मलाल नहीं है, लेकिन हम अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़े हैं।

महोदया हमारे एक भाई ने कहा कि छोटा नागपुर का उन्होंने जिक्र किया कि छोटा नागपुर में भी आदिवासियों की की जमीन छीनी जा रही है। यह बात सही नहीं है गौतम जी को अपना थोड़ा हिसाब-किताब दुरुस्त कर लेना चाहिए। छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट है। जिसके तहत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता लेकिन साहूकारों का जाल जरूर चलता है और साहूकार तरह-तरह का धंधा करके आदिवासियों से ही आदिवासी का उतखात कर रहे हैं। यह बात सत्य है और यह हर जगह हो रहा है पूरे देश में हो रहा है। जंगल की कटाई भी हो रही है। जंगल की कटाई में आदिवासियों का हाथ नहीं है उसमें तो बड़े-बड़े व्यापारी, बनिया और सरकार के शह में यह सारा काम होता है और आदिवासी, वनवासी जिनके जीवन का मूल आधार वनस-पद्धार्थ था उनको उससे वंचित किया जा रहा है। तो सरकार को अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करना चाहिए और त्रिपुरा में तात्कालिक दृष्टि से वहां फेमिन कोड लागू करके जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको लाल कार्ड देकर, कब किसका राशन काड, एक भाई ने कह दिया, एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि जितनी आबादी है उससे ज्यादा राशन कार्ड इश्यू हो गया और राशन कार्ड को वापस लीजिए, और लोगों को बांटिए। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो यह बात तो महोदया, होने वाली है नहीं। इस दिल्ली शहर में ही जितना राशन कार्ड है उससे कई गुना ज्यादा फर्जी राशन कार्ड हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि वहां फेमिन कोड लागू करके तत्काल जो भूखे मर रहे हैं ऐसे लोगों को राशन कार्ड देकर प्राथमिकता के आधार पर अनाज मुहैया कराया जाए। जैसे 1977 में मोरारजी भाई देसाई ने अनाज के बदले काम देकर रोजगार मुहैया कराने की कोशिश की थी उसी तरह से कोई कार्यक्रम अपनायें, क्योंकि हमने यह देखा एन.आर.ई.पी., आई.आर.डी.पी., जवाहर योजना ये सारी योजनायें कागजों पर धरी रह गई, सचमुच में जमीन पर कोई उतरी नहीं। इसलिए जमीन पर उतर कर कोई काम करे। अगर सरकार का सचमुच में कुछ करने का इरादा हो और अगर इरादा नहीं हो तो हम भी यहां अपनी बात रखेंगे, हमारे दूसरे माननीय सदस्य भी रखेंगे, प्रस्ताव पर बहस हो जाएगी, सरकार का कुछ उत्तर हो जाएगा, इस ा कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो यह बहुत ही दुखद बात होगी।

महोदया मुझे बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam Vice-Chairman, though I disagree with the contents of the Resolution moved by the hon. Member, Shrimati Sarala Maheshwari, relating to Tripura, I speak on the Resolution. She has mentioned that this House expresses its serious concern over the large number of deaths in the tribal areas of Tripura due to starvation and hunger related diseases. This is the main theme of the Resolution and she has suggested some ways and means. But if you look at the reality you can see that the deaths that took place in Tripura are ont because of starvation; they are not because of other related diseases. They are duc to gastroenteritis. Chamnu district of Tripura is a hilly area where people can reach only by treakking. The population of that area is about fifty thousand. Because of the monsoon failure the stream from which people in that area draw water got contaminated

[Shri V. Narayanasamy]

and because of that some of the people who took that water died. But the hon. Member has distorted the whole issue by saying that these are starvation deaths. Madam, I would like to say that it is a known fact that the Government is taking steps to provide drinking water through pipelies to the people living in the hilly tracks. They have to use wells and other storage faciilties which are available there. If water is stored there, that can be used for drinking. Unfortunately, people living in the hilly tracks have been taking water which was contaminated. That was the reason for the outbreak of gastroenteritis. Immediately after the disease brokeout, the people living in the Chittagong hill track migrated to that area and so many people died. The hospital is situated about 40 kilometres away from the village where the tragedy took place. Thereafter the medical facilities have been provided. The Agriculture Minister and the Health Minister of Tripura camped there and say the relief operations for giving relief to the people who have been affected by gastroenteritis Madam, in our country natural calamities are there. Apart from that we see that people living in the tribal areas are mostly uneducated. They do not knew about hygiene. Whenever any disease occurs in the tribal areas, medical attention is given to them. But sometimes they refuse to take the medical aid and as a result they die. Every year we have been hearing that in the Koraput district tribal people are dying of starvation. Even last year we came to know that because of monsoon failure in the Koraput district people went to the extent of eating roots of the trees for survival. Whether it is a Congress-ruled State or Opposition-ruled State when even a natural calamity is there, it is the duty of the Government concerned to provided relief to the affected people. Recently in Madhya Pradesh also cholera broke out and more than 200 people died. The Chief Minister said that it had happened and remedial measures had been taken. Therefore, blaming the Government by bringing a resolution saying that it is a starvation death, is a clear distortion. Why do I say this? It is clear that the Chief Minister of Tripura has immediately written to the Prime Minister to send additional medical teams for the purpose of curing the disease. Apart from that, some Ministers of Tripura Cabinet camped there for providing relief operations. But the basic difficulty is, Tripura is situated on our border with Bangladesh. Foodgrains which are provided by the Government of India under the subsidy scheme have been smuggled out by vested interests. People who are eligible to get it are not getting it. So, a system failure is there. Proper distribution of foodgrains is to be done by the concerned State Governments. Goods are being smuggled to Bangladesh by vested interests, by traders and other people. Therefore, it is pertinent that the Tripura Government and also the Government of India should see that food items. which have been given for each unit reach the people of that area and the people get their ration properly. Apart from that the resolution says, the quantity of the commodities presently being supplied through the Public Distribution System should be doubled.

Madam, there is no such demand from the State Government for additional supply of foodgrains. Madam, it is a fact that jute cultivation in Tripura failed because of monsoon failure. It is a hilly region and in the entire North-Eastern region jute cultivation is in vogue. Because water cannot be stored, wherever water is available, wherever there is fertile land, the population moves there. They move from one place to another. They do their cultivation in the hilly tracks and that is their livelihood. That being the case when there is monsoon failure in one area and in the other areas there is a good harvest, in such cases the State Govern-

ment takes care of the people who could not get a good harvest. These people are supplied with foodgrains. But the hon. Member asks as to what was the quantity of foodgrains that was supplied to these people and why it is insufficient and as to why it is not distributed to them properly? Secondly, the hon. Member says that Rural Employment Schemes should be launched on a large scale. I agree with her on this point because when jute cultivation fails, the tribal people have no other vocation. They survive by eating only vegetables that are available there. For their survival they need to be employed and employment schemes have to be implemented in all earnestness in the tribal areas.

Madam, I feel very proud to say that late Shri Rajiv Gandhi, our former Prime Minister had given foodgrains to the tribal people on subsidised rates. Foodgrains were given at 1/3 rates. This scheme was started by Shri Rajiv Gandhi and the scheme is still being continued. Therefore, saying that the Public Distribution System has to be doubled is not correct. If they demand for more supply of foodgrains, the Central Government has buffer stocks and it is prepared to give any State which might require it. As far as Rural Employment Scheme is concerned, employment should be given to the people of hilly regions so that they are able to earn their daily bread. I agree with the hon. Member on this point. As far as medical relief for treating the people suffering from hunger related diseases is concerned, I don't agree with the hon. Member. They are being treated for water borne diseases. It appeared in the papers and it was very categorically stated that the people died because of water borne diseases since they consumed contaminated water. This does happen in some of the areas in the State. Even after 42 years of independence, more than 30000 villages have not been provided with potable water. Even now, in spite of the Five Technology mission, potable water could not be provided to all the villages. The Resolution that has been moved by the hon. Member is politically motivated. A Resolution whenever is brought in this House by any private Member should relate to facts. But as far as my knowledge goes the Resolution that has been brought here has twisted the facts. The State Government has taken all possible steps and they have approached the Prime Minister. The State Ministers are camping there. Relief operations are being provided. Only on one point I agree with the hon. Member and that is on the Rural Employment Scheme. Funds have to provided. As far as other aspects are concerned, about relief operations and foodgrains, they are being sufficiently given. The smuggling of foodgrains from Tripura to Bangladesh should be stopped and it has to be stopped by the State Government with the assistance of the Central Government I totally disagree with the Resolution moved by the hon. Member especially on points like people died due to starvation. The deaths have occurred because of hunger is totally wrong and distorted. I disagree with the Resolution. With these words I conclude. Thank you.

श्री मोहम्मद सलीम : माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया, श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने जो संकल्प यहां उपस्थित किया है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं।

हमारे बहुत से साथियों ने इस संकल्प के ऊपर बहस में हिस्सा लेते हुए बहुत किस्म की रोशनी डाली है। मैं पिछले हफ्ते त्रिपुरा गया था और हमारे बहुत से साथी जो कह रहे हैं—चूंकि अखबार में लिखा गया इसलिए इसको माना नहीं जा सकता, तो मैं वहां दक्षिण त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा, पश्चिमी त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में गया था, जहां वहां के आदिवासी आज भूख की वजह

[श्री मोहम्मद सलीम]

से, दाना न मिलने के कारण नरम ? आक उबालकर खाने को मजबूर हो रहे हैं। पीने को सुथरा पानी न मिलने के कारण वह पहाड़ पर जो छोटा नाला होता है, उसका पानी पी रहे हैं। मुझे यह नहीं मालूम था कि सदन में बैठे हुए हमारे बहुत ज्ञानी साथी इन तमाम बातों से भी इंकार करेंगे। अगर ऐसा होता तो मैं बोतल में वह पानी ले आता और उनको पीने को मजबूर करता। दिल्ली में यहां जो बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने देश को चलाने की जिम्मेदारी ली है, हमारे मुल्क के आदिवासी, जनजाति लोग किस हालत में हैं, उससे वे मुंह मोड़ना चाहते हैं, सच्चाई की तरफ खुली आंख से देखने से घबराते हैं और यही कारण है कि यहां बैठकर हम संकल्प पर बात कर रहे हैं। लेकिन अहलुवालिया जी कह रहे थे कि भूख से लोग कहां मरे हैं, वह तो गैस्ट्रो एन्ट्राइटिस से मारे गये हैं। जिन्हें खाने को भोजन नहीं मिला, पीने का साफ-सुथरा पानी नहीं मिला, जिनको आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज या विलिंग्डन के नर्सिंग होम में जाने की इजाजत नहीं, प्राईमरी हैल्थ सेंटर जिनके लिए बंद कर दिया गया है और अगर उनको हफ्तों तक खाना नहीं मिले, घास-पत्ते और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया जाये, उनको अगर गैस्ट्रो एंट्राइटस नहीं होगा तो क्या होगा ? कृषि मंत्री जी यहां हैं। कोई खबर है वहां के आदिवासी गरीब लोग झूट की शक्ल में खेती करते हैं और जो खेती वहां होती है वह उनके लिए पूरी नहीं है। वहां बासमती चावल नहीं उगता, जो हम बेचकर विदेशों से फारेन एक्सचेंज ले आयेंगे। इसलिए वह दायरा कृषि मंत्री के दायरे से बाहर है। चाहे वहां खेती जल जाए सूखे के कारण, उससे इनको कोई सिरदर्द नहीं होता। आज भी आदिवासी पुराने तरीके से खेती करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह अपनी फसल गरीबी के कारण, बजार न मिलने के कारण, उनको सही कीमत न मिलने के कारण उन्हें पानी की कीमत पर बेचनी पड़ी है। बहुत से लोग, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा था, हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों ने वामपंथी जमाना और अभी यह कांग्रेस के जमाने से कम्पेयर करने की कोशिश की। बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि कम्पेयर किया जाए। किस नजर से वह लोग देखते हैं आदिवासी क्षेत्र को ? किस तरह से आदिवासियों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं ? उनको इंसान का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं हैं तो खुराक क्या देंगे ? पिछली बार जब सूखा पड़ा था, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस रियासत में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कालाहांडी में आदिवासी घास-पत्ते के सहारे जीने को मजबूर हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि आदिवासी कब चावल, चिकन और चाऊमिन खाते थे, वह तो घास-पत्ते ही खाते हैं। यह उनका नजरिया है। आज भी बच्चे बेचे जा रहे हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता सरला जी जो कुछ कह चुकी हैं लेकिन हम दिल्ली में बैठे लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। वहां के लोगों के पास काम नहीं है। मैं अमरपुर गया था, साऊथ त्रिपुरा में, वहां पहुंचा, यहां बैठकर गोल-मोल बात करना आसान है कि देश की गरीबी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है। अरे उन आदिवासियों के जरिये वहां जो जरूरत अनइम्प्लायमेंट खत्म करने के लिए जो स्कीमत हैं, उनको लागू कीजिए। मैं वहां इन्क्लाब करने के लिए नहीं कह रहा आपको लेकिन वहां फड फार वर्क चालू कीजिए। सूखा पड़ने के कारण उनको जो किल्लत हो रही है, अनाज नहीं मिल रहा है, आप उनको काम में लगाइये और अनाज दीजिए ताकि उनको बच्चा बेचकर अनाज खरीदने के लिए मजबूर न होना पड़े। उसके पास पैसा नहीं है; खाद्य नहीं है, काम नहीं है। अभी अब तो बारिश आ रही है। बीमारी शुरू हो चुकी है, पेट की तमाम बीमारियां हैजा हो, कालरा हो, गस्ट्रो-इनटाइटिस हो। मैं खुद लाश देखकर आया हूं। कहते हैं कि पेट की बीमारी से मौत हो गई। अक्सर यह कहा जाता है कि मौत कार्डिऐक अरेस्ट के कारण हुई, उसका हार्ट चलना बंद हो गया, इसलिए हुई अरे पिछले एक महीने, दो महीने,

तीन महीने उसको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। हैजे से जो मारे गए, तीन साल के बच्चे, मैं उनकी लाश देखकर आया हूं। उनका चेहरा बता रहा है कि इतने महीनों से उनको कुछ खाना नहीं

यहां बात आई कि जितनी वहां जरूरत है उससे ज्यादा खाना दिया जाता हैं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं। कल जब आई.टी.बी.पी. के बारे में बात हुई, आपकी सरकार है, रोकते क्यों नहीं है? मैं खुद देखकर आया हूं। वहां के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसलिए कहते हैं कि बैलगाड़ी में सामान जा रहा है, त्रिपुरा में बैलगाड़ी नहीं चलती। वहां हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश की तरह बैलगाड़ी नहीं चलती क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। मैंने खुद देखा है कि गांव के लोग कटहल साइकिल में बांधकर बाजार ले जा रहे हैं। बाजार में उसको जीप में लादा जा रहा है और वह फिर बंगला देश पार हो जा रहा है। वहां से उसकी कीमत मिलेगी। वहां के लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं कि वह उस कटहल को खरीदकर खा सकें। इसलिए वह पैसे के लिए बंगला देश भेजा जा रहा है।

एक तरफ त्रिपुरा में खाने की किल्लत है, दूसरी तरफ राशन की दुकानों के मालिक लोग, सरकार कोई बंदोबस्त नहीं कर सकती, सजा नहीं दे सकती? फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर यहां हैं। मैं साऊथ त्रिपुरा में गया। लोगों ने मुझे सरकारी आदमी समझकर घेर लिया और कहने लगे कि हमारे डीलर ने हमारे कार्ड रख लिए। कहते हैं कि एक हफ्ते का आधा राशन हम देंगे लेकिन कार्ड हमें दे देना पड़ेगा। फर्जी कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। डीलर्स लोग काला-बजारी कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, आपकी मैं तवज्जह चाहूंगा। आप खुद कह रही थीं कि जब आप हरियाणा में मिनिस्टर थीं तो राशन की दुकानों पर यह गलत काम चल रहा था और उसकी रोकथाम का कैसे बंदोबस्त किया गया। मैं चाहता हूं कि आप त्रिपुरा के फूड मिनिस्टर को कहें कि हर राशन की दुकान के पीछे वे एक आल पार्टी बनायें, सुपरवाइजरी कमेटी, जो यह देखे कि राशन के डीलर कैसे चोरी कर रहे हैं ताकि चोरी रोकी जाए और जिनको राशन मिलना चाहिए, उनको मिले और जब उनके पास पैसा नहीं है तो सरकार ऐलान करे डबल राशन का। जब राशन में सामान नहीं होता है तब अक्सर यह प्रैक्टिस है। हमारे यहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा है कि वह ड्यू स्लिप देते हैं। अभी यह स्लिप ले जाओ। बाद में सामान मिलेगा। अगर उनके पास खाना नहीं है तो पहले उनको खाना देने का बन्दोबस्त करो जब उनके पास काम आ जायेगा, वह पैसा चुकता कर देंगे। लेकिन एक हफ्ते, दो हफ्ते का सामान उनके पास एडवांस दिया जाय। खाने के बाद जब उनको ताकत आयेगी तो वह काम करेंगे और आपका पैसा चुकता कर देंगे। अब वहां पर बारिश का समय है। बारिश होने के बाद वहां पर कम्यूनिकेशन बन्द हो जायेगा। रास्ता नहीं है। रेल लाइन नहीं है, सड़क नहीं है। जब बारिश हो जायेगी तो आदिवासियों के जो मनु हैं जिनको गांव कहते हैं वहां अन्दर-अन्दर 20–20 मील, 30–30 मील जाना पड़ता है पैदल। कौन ले जायेगा खाना वहां? अगर खाने का तुरन्त स्टोरेज नहीं किया जायेगा, हर ब्लाक में, हर डिस्ट्रिक्ट में तो उनको खाना कहां से मिल पायेगा। अभी से खासकर इस ओर तवज्जह देकर बारिश से पहले सरकार ध्यान दे। यह बहुत जरूरी है कि वहां पर ब्लाक हैडक्वार्टर में अनाज का स्टोर किया जाय ताकि जब बारिश हो जायेगी तो दो तीन महीने ऐसे वहां होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना मुमकिन नहीं होता, तो लोगों को कम कम से खाना मिल जाय।

स्मगलिंग की बात आई। मैं फिर कह रहा हूं कि उधर ध्यान देना जरूरी है। कल भी मैंने होम मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाई थी आई०टी०बी०पी०

[श्री मोहम्मद सलीम]

के बारे में बोलते हुये। कि स्मगलिंग की रोकथाम करने के लिये राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को बैठाकर काम करना चाहिये। इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, बंगला देश से लोग आ रहे हैं। वहां से जो चकमा रिफ्यूजी आकर बैठे हुये हैं उनको हटाने के लिये हमारे गृह मंत्रालय या त्रिपुरा सरकार किसी की सिरदर्दी नहीं है। उनको वोट ज्यादा अच्छा लगता है। वह कस हालत में पड़े हुये हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो हमारे साथी इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, जो आसाम के बारे में, बंगाल के बारे में कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, त्रिपुरा में आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों के अन्दर हंगामा पैदा करने के लिये वहां की सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से लोगों को बंगला देश की ओर से लाकर बसाया जा रहा है। इतनी गुरबत की हालत में भी बंगला देश से लोगों को बसाया जा रहा है। इसकी रोकथाम सरकार को करनी चाहिए।

जो परेशानियां आदिवासियों की हैं उनको हम किस नजर से देखते हैं, यह ध्यान देने की बात है। पूरे देश में जहां, गंगा, यमुना के इलाके में ये लोग बसते थे, जो कमजोर वर्गों के लोग थे उनको वहां से धकेला गया, मारा गया, भगाया गया। जब इन इलाकों में खेतीबाड़ी होने लगी, आज जो बड़े बड़े अपने को किसान नेता कहते हैं उन्होंने इन आदिवासियों को जहां फसल ज्यादा होने की गुंजायश थी वहां से धकेल दिया। जो विकास के नाम पर विज्ञान आगे बढ़ा, जब नये नये प्रोजेक्ट आये तो ऐसे इलाकों में भी जहां पहले हम कदम नहीं रखते थे, चाहे वह पानी का इस्तेमाल हो, हाइड्रो-इलेक्ट्रिक के लिये हो, चाहे जमीन के नीचे की जो क्षमता है उसके व्यवहार के लिये हो, वहां भी आबादी बसाने की जरूरत पड़ गई और आज हम वहां जा रहे हैं। यह सिर्फ त्रिपुरा का सवाल नहीं है, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, इन तमाम ट्रायबल इलाकों में विकास के नाम पर एक नई आफत आ रही है। बाहर के लोग न अपने कल्चर को न अपनी संस्कृति को उनके साथ मिला पाते हैं, लेकिन उनके ऊपर वह जबरदस्ती लादी जा रही है। कांट्रेक्टर, पुलिस और पोलिटीशियंस को जो नेक्सस है वह आदिवासियों कि ऊपर जुल्म ढा रहा है। यही कारण है कि उनके अन्दर आज टेंशन पैदा हो रहा है, विरोध पैदा हो रहा है। वह अपने को इस व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। उनके ऊपर हमारी नीतियां चाहे वह अर्थ नीति के नाम पर हो, उद्योग नीति के नाम पर हो, साम्राज्यवादी जो नीतियां हैं, मल्टीनेशनल जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उनके कारण और भी आफतें आने वाली हैं

मध्य प्रदेश का जो आदिवासी इलाका सरगुजा है वहां पर आदिवासी लोग मर रहे हैं, त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी मर रहे हैं या महाराष्ट्र के थाणे जिले में आदिवासी मर रहे है, यह किस चीज की निशानदेही करती है हम जो पालिसी ला रहे हैं इसका फलसफा यह है कि पैसा फेंको और तमाशा देखो। बंगला में कहते है अगर कोड़ी फेंक सकते हैं तो सिर से लेकर पैर तक तेल फेंक सकती हैं सरकार या कोई भी संस्था अगर कोड़ी फेंक नहीं सकते तो तुम्हें तमाशा देखने का हक नहीं है। इसी कारण से जो सबसे ट्राइबल इलाका है, सबसे कमजोर तबका है उसके ऊपर यह पहली आफत आई है। जब भी कोई ऐसी आफत आती थी तो सरकार हिलती थी। उस अकाल ग्रस्त इलाके में रिलीफ भेजी जाती थी। उसके तहत राहत कार्य होता था लेकिन अब सरकार कोई काम नहीं करती क्योंकि नया फलसफा आ गया है। इसमें सरकार वही काम करेगी जिसमें उसको फायदा होगा। त्रिपुरा के उन आदिवासियों को पानी पिलाने से मनमोहन सिंह को या मल्टीनेशनल कम्पनीज को कोई फायदा होने वाला नहीं है इसलिए पानी वहां नहीं पहुंचेगा। आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए है उन चुनाव के समय यही लिखा होता है कि हर गांव में पीने के पानी का प्रबन्ध किया जायेगा लेकिन आज

भी वहां पीने को पानी नहीं मिलता है। अगर हमें पाली पैक में व्हीस्की बेचने से फायदा होगा तो सरकार वह व्हीस्की बेचेगी क्योंकि विश्व बैंक और आई.एम.एफ. ने कहा है वही काम करना है जिसमें उनको फायदा है। हम यह कहते हैं उन फायदों से क्या फायदा जिसमें हमारे देश की मातायें अपने बच्चे को, एक साल के बच्चे को बेचें क्योंकि खुराक न दे पाई और हम यहां कहें कि हमारे पास बहुत खाना है लेकिन हम वहां भेज नहीं पाये। सिलचर में एफ०सी०आई० के गोदामों में, जैसा सी.पी.आई. के लोग कह रहे हैं कि लाखों, करोड़ों का सामान त्रिपुरा में भेजने के लिए, मिजोरम में भेजने के लिए, मेघालय में भेजने के लिए स्टोर किया जाता है उसमें चोरी हुई। बड़े-बड़े पोलिटिशंस उनको सहारा देते हैं। चोरी करने वालों को सहारा देते हैं। तो वहां खाने के बगैर नहीं मारे जायेंगे तो क्या होगा। स्मगलिंग होती है, खाने के सामान की चोरी होती है। आदिवासियों की पिछड़े क्षेत्र में क्या हालत होगी आप जान सकते हैं। इसलिए मैं यह मांग करता हूं और संकल्प में यह मांग दी हुई है कि हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। यह कोई मेरी बात नहीं है, पहली बात नहीं है, हमारी कांग्रेस पार्टी की जो हुकूमत आई है उसने अपने मेनिफेस्टो में यह कहा था कि दे विल स्ट्रेंगथन द पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मोहम्मद सलीम: प्रधान मंत्री जी ने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को नये तरीके से ट्राइबल ब्लाक को आइडेंटीफाई करके चालू करने के लिए कहा। कितने ब्लाक आइडेंटीफाई हुए हैं त्रिपुरा के अंदर? कितने लोग वहां मारे जा रहे हैं? अगर ट्राइबल बेल्ट में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मजबूत करके आइडेंटीफाई किया तो वहां का हिसाब दीजिए। कांग्रेस के साथी वहां गये थे। साउथ त्रिपुरा, नार्थ त्रिपुरा और वेस्ट त्रिपुरा के अंदर कितने आदिवासी ब्लाकों को लिया गया? जो सामान भेज रहे हैं वह किस हद तक आदिवासियों के पास पहुंच रहा है?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): समाप्त करिये आपका समय समाप्त हो चुका है। चार मिनट ऊपर ले चुके हैं। कृपया समाप्त करिये।

श्री मोहम्मद सलीम: माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं त्रिपुरा खुद गया था और जो वहां पर....

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): 15 मिनट से आप वही तो जानकारी दे रहे हैं जो देख कर आये।

श्री मोहम्मद सलीम: समय से इसे नहीं मापा जा सकता। जो मंत्रिमंडल के अहम मंत्री हैं वे यहां बैठे हुए हैं। यह चर्चा ढाई बजे से चल रही है। वे दूसरे सदन में जरूरी काम से व्यस्त रहने के कारण यहां नहीं आ पाये मैं उनकी नजर में यह बात लाना चाहता हूं। मैं आपसे यह भी मांग करता हूं यदि जरूरत पड़े, इसे आज खत्म नहीं कर पाये तो आने वाले दिनों में इस पर बहस हो।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): यह तो चलेगा लेकिन आपका समय तो समाप्त हो गया।

श्री मोहम्मद सलीम: जो संकल्प है उस विषय के अंदर ही बोल रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): विषय के अंदर तो बोल रहे हैं लेकिन समय के अंदर भी बोलिए। समय की परिधि में बोलिए। विषय पर बोल रहे हैं मैं मान रही हूं लेकिन समय की परिधि में बोलिए। समय का ध्यान रखिये।

श्री मोहम्मद सलीम: वहां पर जो ग्रामीण रोजगार योजनायें हैं उनको लागू किया जायें। त्रिपुरा के लोगों की यह शिकायत है कि वहां जो स्कीमें चल रही हैं उनका फायदा उनको

[श्री मोहम्मद सलीम]

नहीं मिल रहा है । इसलिए केन्द्रीय सरकार बन्दोबस्त करे कि जो वह मैचिंग ग्रान्ट देती है उसको सही ढंग से मोनीटर करे । कुछ अफसरों और मंत्रियों की बात पर ही न चलें । वहां पर अपनी टीम भेजें और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अपनी टीम भेजे और सब चीजों को देखें । अभी कमला जी ने फूड प्रोग्राम की बात कही है । उसकी तरफ ध्यान दिया जाये ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी बरसात आने वाली है । वहां पर बरसात में रोग शुरू हो जाते हैं । पानी की किल्लत रहती है जिससे बीमारियां फैलती हैं । इसलिए रोगों की रोकथाम के लिए काम किया जाय । वहां पर जो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं उनकी हालत अच्छी नहीं हैं । वहां के लोग लाचार हैं । यह किसी पार्टी पोलिटिक्स की बात नहीं है । यह देश प्रेम की बात है । चुनावों के वक्त जिस प्रकार से आप लोगों को सम्बोधित करते हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिये । वहां जनता भूखों मारी जा रही है । आप कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं करेंगे तो वही स्थिति पैदा होगी । अगर कोई कदम नहीं उठाये गये तो वहां के नवजवान गलत रास्ते पर चले जायेंगे जैसा कि आप कुछ नार्थ-ईस्टर्न स्टेटों में देख रहे हैं । त्रिपुरा में भी उनको तरह तरह के नाम देकर भड़काया जा रहा है । ये लोग वहां के नवजवानों को दूसरी और खींच लेंगे और व्यवस्था के विरुद्ध नहीं, बल्कि देश के विरुद्ध लड़ा देंगे । इसलिए मेरी विनती है कि आप इस तरफ ध्यान दीजिये । दिल्ली में तो हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं । लेकिन वहां पर खुराक की बात है, पीने के पानी की बात है । आप वहां की राज्य सरकार को मजबूर करें कि वह काम करे । लड़ने-झगड़ने की बात तो होती रहती है, लेकिन वहां के आदिवासियों के विकास के लिए काम होना चाहिए । वहां पर आपकी पार्टी की ही सरकार है ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया । माननीय सदस्या श्रीमती सरला माहेश्वरी जी जो प्रस्ताव लाई हैं वह भूखमरी और भूख से संबंधित रोगों के कारण त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जो मौतें हुई हैं उससे संबंधित हैं । मगर हमने समाचार पत्रों में पढ़ा तो हमें यह पता जरूर लगता है कि मौतें जरूर हुई हैं, लेकिन वे भुखमरी से नहीं हुई हैं । गस्ट्रो-इनटराइटीस नाम की जो बीमारी है उसके कारण हुई हैं । किसी भी प्रदेश में जहां के लोगों को आरोग्य रखना वहां की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है । वहां जो मौतें हुई हैं वह ठीक नहीं हैं । अन्य प्रदेशों में भी हैजे और इस प्रकार की बीमारी से मौतें होती हैं । हमारे महाराष्ट्र में बम्बई जैसे शहर में भी इन रोगों से मौतें हो जाती हैं । इन रोगों के खिलाफ मनुष्य की लड़ाई चल रहीहै । लेकिन मनुष्य जिस प्रकार से नई नई दवाइयां पैदा करता है, औषधियां निकालता है, उसी तरीके से, उसी गति से, नई नई बीमारियां भी पैदा होती रहती हैं । कुछ दिन पहले इसी सदन में प्रश्नोत्तर काल में चर्चा हुई थी कि एड्स की बीमारी बढ़ रही है । उसके बारे में वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि — By the turn of the century, India will be the most affected country in the world by the disease called AIDS. ऐसी उसकी रिपोर्ट है । जैसे-जैसे मानव प्रगति की तरफ जाता है वैसे वैसे नए नए जीव-जन्तु भी प्रगति की तरफ जाते हैं ।

गस्टोइंटराइटिस जब होता है, इसके किटाणु भी मनुष्य के शरीर में जो अनाज या ऊर्जा देने वाले साधन होते हैं, उसे खाते हैं और उससे मनुष्य का अन्त हो जाता है । तो यह बात भी ठीक नहीं है, इसके बारे में सरकार को उचित कदम उठाना चाहिये । सरकार का यह कर्तव्य बनता है । सरला माहेश्वरी जी बड़ी अच्छी संसद सदस्या हैं । वे जो प्रस्ताव लाई हैं, यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है । इसके पहले पांच साल तक वहां सी०पी०एम० की सरकार थी और अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है । यह कोई जरूरी नहीं है कि सी०पी०एम० की सरकार में कोई डकैती नहीं होती, यह कोई जरूरी नहीं है कि सी०पी०एम० की सरकार जहां रहेगी तो कोई मौत नहीं

होती, बीमारी नहीं होती। यह बात जरूरी नहीं है। यह चीजें सारी पार्टियों की सरकारों के जमाने में चलती रहती है क्योंकि यह समय की मांग है और यह होता रहता है। मगर जो प्रश्न उन्होंने उठाया है, इस प्रस्ताव में जो दूसरी बात उन्होंने कही है वह यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मारफत सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा दुगनी की जाए। मैंने सुना है कि वहां की पापुलेशन 75 हजार है। पता नहीं, मैं तो त्रिपुरा का रहने वाला नहीं हूं, यह कम या ज्यादा भी हो सकती है, मगर उससे ज्यादा राशन कार्ड है। इसका मतलब यह है कि जब ज्यादा राशन कार्ड होते हैं तो उसमें हेराफेरी जरूर होती है। हेराफेरी करने वाले लोग चाहें कांग्रेस का राज हो या कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो या किसी अन्य पार्टी का राज हो, यह तो एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, इसलिये इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिये। वहां एक लाख राशन कार्ड हैं और जनसंख्या उससे कम है। यह राशन कार्ड देने वाला जो अधिकारी है या जो मंत्री है उसके खिलाफ जरूर कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिये। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। यह भी देखा गया कि हमारे हिन्दुस्तान के इतिहास काल से लेकर आज तक एक ही जमात है जो सारे देश को लूटती रहती है वह है मिडलमैन। जो ट्रेडर है वह सारी मलाई खुद खा जाते हैं और गरीबों के पल्लु में भूख डाल देते हैं, गरीबी डाल देते हैं। यही सब से बड़ी बीमारी है। इसको हटाना हमारी सरकार का और सारे देश का नैतिक कर्तव्य है। सारी पार्टियों का नैतिक कर्तव्य है। सरकार अनाज लेती है और मुख्य मंत्री को भी कोई शिकायत नहीं है कि वहां फूडग्रेंस की सप्लाई कम है लेकिन वह अनाज यदि गरीबों को नहीं जाता है, आदिवासियों की तरफ नहीं जाता है तो यह बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ऐसा मैं मानता हूं। मैं एक्सट्रीम वैस्ट का रहने वाला हूं और त्रिपुरा एक्सट्रीम ईस्ट में है, मैं उस पर बोल रहा हूं। चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, मनुष्य का स्वभाव एक ही तरह का है, स्वार्थ का है। इसलिये जब तक मनुष्य अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों की भलाई के लिये नहीं सोचेगा तब तक हमारे देश में कोई भी योजना अच्छी तरह से नहीं हो सकती है। यह बिलकुल सिद्धांततः बात है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके बारे में भी मास एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरी बात जो उन्होंने बताई है वह भी काफी सराहनीय है कि व्यापक स्तर पर ग्रामीण रोजगार योजनायें शुरू की जायें। यह तो बहुत जरूरी है। आदिवासी इलाकों में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कई सदियों से पिछड़े हुए हैं और एक्सप्लायटेड हैं। यह बात कोई जाति की बात नहीं है। यह वह जाति है जिसे सदियों से लेकर बड़े लोगों ने एक्सप्लायटेशन किया है, गरीब रखा है, इनको ऊंचा उठाना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है। जहां तक हमारी सरकार है, श्री पी०वी० नरसिंह राव की सरकार है, आज ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह कहा कि पहली बार आठवीं पंचवर्षीय योजना में 30 हजार करोड़ रुपये ग्राम सुधार के लिये रखे गये हैं। यह बहुत जरूरी उपलब्धि है। हमारी सरकार की नीयत क्या है, इसको देखना चाहिये मगर आपको हमारी सरकार की नीति पर भरोसा नहीं है तो चाहे हम आपको किन्हीं शब्दों में भी समझायें आप बिलकुल समझने वाली नहीं हैं क्योंकि आपको पक्का विश्वास है कि जब तक यह सरकार नहीं जायेगी। आपकी भी सरकारें थीं। 1977 से लेकर 1980 तक आपकी सरकार थी। ढाई साल में आपने आपस में कितनी बार झगड़ा किया और कितना काम किया, यह सारे देश और दुनिया के सामने है। बाद में आपकी सरकार फिर आई, पहले 11 महीने का प्रधान मंत्री रहा फिर बाद में 5 महीने का प्रधान मंत्री रहा। उन्होंने क्या किया है, यह भी देश के और आपके सामने है। देश की हालत ऐसी बन गयी थी कि कि जहां हमारे पास

1500 करोड़ का फारेन एक्सचेंज था वहां हमें 5 हजार करोड़ का देना था। दुनिया में कोई भारत को अच्छा देखने वाला नहीं था। भारत सरकार को कोई दूसरा उपाय नहीं था। सारा क्रेडिट और सारी साख उन्होंने गंवा दी थी। अब सवाल यह था कि भारत वह साख कैसे कायम करे।

ऐसी जो करप्शन की बातें होती हैं, वे तो आपके जमाने से चली आ रही हैं। यह कोई नयी देन नहीं है। ये आपके जमाने में भी हुई है। 1977 से लेकर 1980 तक के जमाने में मैं जानता हूं कि मैंने खुद अपना 3 एकड़ का गन्ना जला दिया। 70 रुपये पर टन गन्ने की कीमत थी और हमारा ट्रांसपोर्ट और कटाई चार्ज सौ रुपये जाता था, तो कारखाने को ले जाने के बजाय हमने खुद खेत जला डाला या अपने जानवरों को डाल दिया। ऐसी हालत आपने बना दी थी। इसलिये आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि कांग्रेस की सरकार के जमाने में ये सारी भुखमरी की स्थिति आई और मौतें हो रही हैं। मौतें तो होती रहती हैं मगर जब मनुष्य के निष्कार्य के कारण होती है तो उन पर जरूर सरकार को पकड़ना चाहिये, उसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिये। उस पर मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना भी सरकार का पवित्र कर्तव्य है। आपको मालूम होगा जब राजीव गांधी की सरकार थी तो जवाहर रोजगार योजना बनी थी। उन्होंने स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के कितने सेमिनार किये और राजीव गांधीजी सबसे ज्यादा ट्राइबल एरियाज में गये तथा सारे आदिवासी क्षेत्रों का अभ्यास किया। उसी की बेसिस पर आज हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार हो रही है। यह तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि गरीबों, आदिवासियों और शैड्यूल्ड कास्ट्स के सुधारों और योजनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर पूरा योगदान करें।

मैं बहुत खुश हूं इस चीजपर कि हमारे जाखड़ साहब इतने अच्छे कृषि मंत्री इस देश को मिले हैं कि जो खुद किसान है। मैं भी किसान हूं, वे भी किसान हैं और किसानों की समस्या का मूल वे जानते हैं, उसका दर्द जानते हैं। किसान और खेत मजदूर ये दो ही जातियां ग्रामीण क्षेत्र में हैं, न कोई हरिजन है, न गिरिजन, न ठाकुर, न ब्राह्मण। खेती करने वाला किसान है और खेत में काम करने वाला खेत मजदूर है और ये एक वृत के दो चाक हैं और जब तक ये ठीक तरह से चलेंगे तब तक भारत की कृषि की नीति और भारत की अर्थव्यवस्था भी ठीक तरह से चलेगी।

सबसे बड़ा प्रश्न हमारे देश के सामने यह है कि हम अपनी कृषि के लिये नियोजन में कितना पैसा दे रहे हैं। 70 प्रतिशत जनसंख्या जिस पर डिपेंडेंट है उस कृषि पर जब तक हम 70 प्रतिशत धन खर्च नहीं करेंगे, कृषि या कृषि उद्योगों पर, तब तक हमारी योजनाओं का हमें कोई यश नहीं मिलेगा, हमें ऐसी उपलब्धि नहीं मिलेगी जिससे भारत की प्रगति हो सके।

मैंने कितनी बार इस सदन में कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो नीति है, जो इक्नामिक पालिसी है वह एग्रो बेस्ड होनी चाहिये। कृषि पर पर ही हमारी राजनीति, अर्थनीती और सब नीति निर्भर हैं। हम अमेरिका, इंगलैंड आदि राष्ट्रों की कभी नकल नहीं कर सकते उनके पास रशिया या भूमि बहुत कम हैं इन्डस्ट्री ज्यादा हैं। पुराना सोवियत यूनियन नाइन टाइम्स हमसे ज्योग्राफिकली बडा है। मगर उनकी कृषि उनकी खेती हमसे आधी भी नहीं है। उनके लिए हमें अनाज भेजना पड़ता है। मगर ईश्वर की दया से हमारे पास इतनी अच्छी भूमि है, पानी है, वर्षा इतनी अच्छी होती है कि हमारे देश में अगर हम कोशिश करें तो हम क्या नहीं कर सकते जैसा कि पुराणों में कहा गया है कि इस भूमि में सोना उगता है . . (**व्यवधान**)

अभी ऐसा भी है कि हमारी जो मैन पावर है, मनुष्य बल है उसका उपयोग, उसका यूज अच्छी तरह से कैसे करें। इस पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जरूर कहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार देने के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसको प्रोयोरिटी देनी चाहिए। मैं जरूर उम्मीद रखता हूं कि हमारे जो कृषि मंत्री जाखड़ साहब हैं वे इस पर जरूर ध्यान देंगे।

5.00 PM दूसरी बात जो माननीय सरला माहेश्वरी जी ने उठाई है कि भूख से संबंधित रोगों से लोगों के इलाज के लिए पर्याप्त राहत उपाय शुरू किये जायें, यह भी काफी अच्छी बात उन्होंने उठाई है। भूख से पीड़ित लोगों में जो रोग होते हैं, जो डिजीजिज होती हैं, उनका भी संशोधन होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में बहुत सारे रोग ऐसे हैं, जो डेफिशेंसी आफ न्युट्रिएंट्स की वजह से होते हैं, अच्छी तरह से खाने के लिए न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, अच्छी तरह से उनकी व्यवस्था नहीं होती, सारी उनकी हाईजीनिक कंडिशंस नहीं होतीं, इसकी वजह से भी काफी बीमारियां होती हैं। (समय की घंटी) तो उसके संबंध में भी हमें काफी अच्छी तरह से सोचना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Private Members' business is over for the day. If you want, you continue your speech next time.

Now, I have the second Supplementary List of Business before me. Paper to be laid on the Table—Shri Shantaram Potdukhe.

PAPER LAID ON THE TABLE—Contd.

Notification of the Ministry of Finance Department of Revenue)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Madam, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification G.S.R. No. 679(E) dated the 17th July 1992, exempting persons who have been resident outside India from the obligation of surrender of their foreign currency assets held abroad when they return to India together with an Explanatory Memorandum thereon. [Placed in Library. *See* No. LT-/92.]

CLARIFICATIONS ON STATEMENT RE. DERAILMENT OF 8033 AHMEDABAD-HOWRAH EXPRESS ON BADNERA-WARDHA SECTION OF CENTRAY RAILWAY

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Now, clarifications on the statement by the Minister of Railways. Shri V. Narayanasamy ...Not here. Shri Ram Naresh Yadav.

श्री राम नरश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, जो रेलवे की यह घटना घटी, वह बहुत ही दुखद और चिंतनीय रही और जो लोग इसमें मरे, उससे इस पूरे सदन की समवेदना है और साथ ही साथ यह है कि आये दिन ऐसा देखा जाता है कि रेलवे की कहीं न कहीं घटनायें हुआ करती हैं। उसमें जानें जाती हैं। उसके बाद फिर बयान हम देते है और बयान देने के बाद फिर वहां से मामला ठंडा पड़ जाता है।

ऐसी स्थिति में जो यहां पर घटना घटी है, पैरा दो में जिस तरह कि जो सरकार को रिपोर्ट मिली और उसके बाद माननीय मंत्री जी गये, दूसरे अधिकारी भी गये, मौके पर जाकर के सारी चीजों को देखा। तो वहां पर जो आया है, वह यह है कि फिश प्लेट्स, नट-बोल्ट्स अप और डाऊन ट्रैक के सब हटा दिये गये थे और फिश प्लेट्स हटा दी गई थीं, सब चीजें कुछ इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं।